● सीधी, रीवा एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित ● website-https://vindhyatiger.in ● epaper-https://epaper.vindhyatiger.in ● वर्ष : 36, अंक 152, पृष्ठ : 08, सीधी, गुरूवार, 11 जुलाई 2024 - मूल्य : 2.00 रुपया मात्र

दैनिक समाचार पत्र

विन्ध्य टाइगर

हक की बात, बुलंदी के साथ

सिद्धारमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किले 5

राहुल द्रविड़ ने जीता दिल 6

साझा वार्ता में पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार

वियना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रिया में हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन के साथ बैठक की। इसके बाद एक ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ संयुक्त वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'भारत और ऑस्ट्रिया, आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं जाएगा। आतंकवाद को किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं हो सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव के लिए सहमत हैं, ताकि उन्हें मजबूत

ऊर्जा-नवाचार और द्विपक्षीय सहयोग पर जोर

बनाया जाए। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति हो, सभी पर हमने विस्तार से बात की। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम बच्चों की मौत स्वीकार्य नहीं है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए वार्ता और कूटनीति पर जोर देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं।'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे ऑस्ट्रिया आने का मौका मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक और विशेष है। 41 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा है। यह भी सुखद संयोग है कि यह यात्रा उस समय हो रही है, जब हमारे आपसी संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों में आपसी विश्वास हमारे संबंधों की नींव हैं। आपसी विश्वास से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने फैसला लिया कि संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी।

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। ढांचागत विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन और क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और विचारों को जोड़ने के लिए स्टार्ट अप को गति दी जाएगी। गतिशीलका और प्रवासन के मामले में साझेदारी पर पहले ही समझौता हुआ है। कानूनी प्रवासनन और कुशल कार्यबल को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया जाएगा। आज मानवता के सामने मौसम में बदलाव और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए।

केन्द्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ : डॉ. यादव

14 जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ होगा शुभारम्भ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रसन्नता का विषय है कि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह आगामी 14 जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। एक्सीलेंस कॉलेजों की विशेषता है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप इनमें सभी कोर्स उपलब्ध होंगे तथा ये कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। युवा पीढ़ी को इन कॉलेजों का लाभ मिलेगा। सभी मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र में कॉलेजों के शुभारंभ कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही। बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम् गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के बजट की सभी ओर सराहना हो रही है।

बजट के जन-कल्याण एवं विकास से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम किए जाएं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों को राजधानी से सीधे जोड़ने के लिए बनने वाले एक्सप्रेस-वे तथा सभी विभागों को उपलब्ध कराई गई पर्याप्त राशि से प्रदेश के विकास पर होने वाले प्रभाव के संबंध में जिलों में चर्चा हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 20 जुलाई को जबलपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए सभी जिलों में सहयोग व मार्गदर्शन कार्यक्रम संचालित किए जाएं। प्रदेश के स्थानीय औद्योगिक इकाई संचालकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें अपनी गतिविधियों का विस्तार करने एवं निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रोत्साहित किया जाए।

जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान: केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (10 जुलाई) को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा- मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल, जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है।

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा- ईडी कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास इन्टेरोगेशन (पूछताछ) नहीं किया। एक राजनीतिक विरोधी को

परेशान और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। मामले को लेकर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अब ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने कहा कि श्रेष्ठ की दलीलें कानून के हिसाब से ठीक नहीं थीं। ईडी की दलीलें असंवेदनशीलता के रवैये को दर्शाती हैं। पीएमएलए की धारा 3 के तहत मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।

तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।

मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

सीएम शिंदे ने कहा-दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

मुंबई। मुंबई की अदालत ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मिहिर को मुंबई पुलिस ने करीब 72 घंटे की तलाशी के बाद मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया था। मिहिर शाह शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राजेश शाह का बेटा है।

सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सेवरी कोर्ट) एसपी भोसले से कहा कि यह एक क्रूर अपराध था। आरोपी को अधिकतम हिरासत में रखा जाना चाहिए। पुलिस ने कहा, यह जांच करने की जरूरत है कि मिहिर को भगाने में किसने मदद की। साथ ही कार की नंबर प्लेट बरमाद नहीं हुई है।

पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें यह पता लगाना है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। कार की नंबर प्लेट का क्या हुआ, जिसे एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने कथित तौर पर फेंक दिया था। वहीं, मिहिर शाह के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने शाह और ड्राइवर से पूछताछ की है। उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मैंने निर्देश दिया है कि मामले में दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजेश शाह को पार्टी से निलंबित करने पर सीएम शिंदे ने कहा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

भोपाल-उज्जैन के बीच 11 जुलाई से चलेगी स्पेशल ट्रेन

भोपाल। भोपाल में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उज्जैन-भोपाल-उज्जैन के मध्य ट्रेन 09313, 09314 स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन 09313 उज्जैन-भोपाल स्पेशल 11 जुलाई से 31 अगस्त तक उज्जैन से प्रतिदिन नौ बजे चलकर मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए अगले दिन 12ः40 बजे संत हिरदाराम नगर और एक बजे भोपाल पहुंचेगी।

सात राज्यों में उपचुनाव, 13 विधानसभा सीटों पर 63 फीसदी वोटिंग

नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार (10 जुलाई) को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। छिटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा-टीमएसी समर्थक बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक-दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मामला शांत कराया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे चौराहे पर खड़े होकर वोटिंग करने जा रहे लोगों को रोक रहे हैं।

उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर झड़प के बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बिहार में पूर्णिया की रुपौली सीट पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पुलिस की माने तो बूथ के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने हटने को कहा तो बहस शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। एक एसएचओ और सिपाही घायल हो गए।

मुंबई में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान, असम में बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून की स्थिति भी अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में भारी बारिश के कारण जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में लोगों को अब भी उमस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मौसम विभाग इन क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में जारी भारी बारिश का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। यहां मंगलवार तक 6.92 इंच बारिश दर्ज की गई। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसके चलते यहां भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही गोवा और

कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी, तो कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। असम में बाढ़ से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 7 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ अब बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 79 तक पहुंच गया। राज्य में 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तीन हजार से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं, ब्रह्मपुत्र सहित 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

पिछले कुछ दिनों से उमस का सामना कर रहे दिल्लीवासियों को इससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने यहां भी बारिश का अलर्ट जारी है। कुछ स्थानों पर हल्की, तो कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिण मध्य प्रदेश के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के नहीं बनने के कारण फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं है।

सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई से हटे जस्टिस संजीव खन्ना

नई दिल्ली। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस खन्ना ने इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है।

जस्टिस खन्ना के अलग होने से रिव्यू पिटीशंस पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पांच जजों की नई बेंच का पुनर्गठन करना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ही इन पर सुनवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 52 याचिकाएं दायर कर फैसले पर पुर्नविचार करने की मांग रखी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पांच जजों की बेंच फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर चैंबर में सुनवाई करने वाली थी।

सिक्किम के एकमात्र विपक्षी विधायक ने पार्टी छोड़ी

गंगटोक। सिक्किम में अब एक भी विपक्षी विधायक नहीं रह गया है। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के इकलौते विधायक तेनजिंग नोरबू लाम्था सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए हैं। एसकेएम के पास अभी 30 विधायक हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इसी साल 19 अप्रैल को सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। 2 जून को आए नतीजे में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती थीं। 25 साल सत्ता में रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक सीट मिली थी।

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दो सीटों से जीत हासिल की थी, जिसमें से उन्होंने एक सीट छोड़ दी। तमांग की पत्नी कृष्णा कुमारी राय ने भी चुनाव जीता था, उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ दी है।

उन्नाव में भीषड़ सड़क हादसा, 18 यात्रियों की मौत

उन्नाव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने दूध कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। अब तक 18 यात्रियों की मौत हुई है। बस में 57 यात्री सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे से दुख व्यक्त किया है। इस बीच, हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

इस बीच, हादसे को लेकर जांच में नए तथ्य भी सामने आए है। पता चला है कि हादसे से ठीक पहले ड्राइवर ने एक ढाबे पर शराब पी थी। इसके बाद वह तेज गति से बस चला रहा था।

वहीं, मृतकों में 11 लोग बीमार के हैं। इनमें भी एक ही परिवार के 6 सदस्य भी शामिल हैं। ये सभी पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के फेनहारा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। फैनहारा थाना क्षेत्र के इजोरवाडा गांव के भी तीन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है।

सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण भाजपा सरकार की लापरवाही है।

इससे पहले डीएम गौरांग राठी ने अपडेट जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, बस में लगभग 57 यात्री सवार थे। सभी को दिल्ली जाना था। 18 की मौत हुई है। 20 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। हमने 6 घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। बाकी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है।

मंत्रि परिषद की बैठक में राज्य शासन के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति कल्याण/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति दरों के अनुरूप युक्त-युक्तीकरण की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार बालकों को वर्तमान में प्रतिमाह देय शिष्यवृत्ति 1230 रुपए में वृद्धि कर 1550 रूपये एवं बालिकाओं को 1270 रूपये में वृद्धि कर 1590 रूपये प्रतिमाह दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर आगामी शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग के लिए भी मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के क्रियान्वयन का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को मध्यप्रदेश विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रूपये की परियोजना का अनुमोदन दिया हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश की समस्त विधान सभाओं को पेपर लेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) लांच की गई है। लागत की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।

नर्मदा घाटी की परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रूपये की लागत की 7 परियोजनाओं के निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है। सोण्डवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, धार माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माईक्रो सिंचाई परियोजना एवं माँ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई है।

बोकारो माइक्रो इरीगेशन की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से तहसील रामपुरा नैकिन के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

इंदौर में केन्द्रीय जेल के शेष रहे कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने इंदौर में सांवेर रोड़ पर निर्माणाधीन केन्द्रीय जेल के शेष रहे निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन दिया गया है। राज्य शासन के लिये अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए मध्यप्रदेश शासन के लिये विमान/हेलीकाप्टर क्रय-विक्रय नियम, 2019 के अंतर्गत बुलाए गए टेण्डर में निम्नतम (स) निविदाकार संस्था से विमान मॉडल चैलेंजर 3500 जेट विमान क्रय किये जाने के निर्णय का अनुमोदन दिया गया।

मोहर्रम त्योहार को सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनाएं : शुक्ला

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित

सिंगरौली। कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला के अध्यक्षता में एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता गुप्ता के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री शुक्ला के द्वारा उपस्थिति सभी सदस्यों, धार्मिक प्रतिनिधियों का स्वगत करते हुए कहा की गतवर्ष के भाति मोहर्रम पर्व को सौहादर्य पूर्ण वातावरण में मनाए सिंगरौली जिले में सदैव सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते है । मुझे आप सबसे पूर्ण अपेक्षा है की मोहर्रम त्योहार को ऐसे ही वातावरण में मनायेंगे। कलेक्टर ने बैठक के बैठक के दौरान निर्देश दिए के जुलूस के दौरान कोई भी शस्त्र एवं धारदार हिथियारो का प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा की जुलूस के दौरान यातायात के नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्गों का चिन्हांकन पहले से कर लिया

जाए जिससे आवागमन में परेशानियां न हो । मोहर्रम का जुलूस पूर्व निर्धारित मार्गों पर ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। कलेक्टर ने मार्गों की मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए । वहीं विद्युत प्रवाह निरंतर बनाए रखने एवं प्रकाश की व्यवस्था हेतु कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए। वहीं आयोजन के दौरान आकस्मिक आपात चिकित्सा व्यवस्था बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ अधिकारी को निर्देश दिए । साथ ही यह भी निर्देश दिए की मोहर्रम त्योहार के दौरान बड़े पैमाने पर दूध , मावा , एवं मिठाई की बिकरी को दृष्टि गत रखते हुए नकली औा मिलावटी मिठाईयों के निर्माण तथा बिक्री पर कार्यवाही किये जाने के उपखण्ड अधिकारियो को निर्देश दिये। बैठक के दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि सभी अनुभाग, तहसील थाना स्तर गठित शांति समिति बैठक आयोजित करे। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती गुप्ता ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कहा कि सुरंक्षा कारण से त्योहार के आयोजन के दौरान शस्त्र एवं धारदार हथियारों का प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। त्योहार के दौरान जुलूस में सम्मलित होने वाले वालेंटियर के सख्या की जानकारी प्रदान करे ताकि सुरंक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये जा सके। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से यह भी कहा कि ताजिएं की उचाई निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हो ताकि जुलूस के दौरान विद्युत तारो में रूकावट न आये। वही उपास्थित सदस्यों को त्योहार के दौरान सुरंक्षा, यातायात नियंत्रण आदि के संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने हेतु अश्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान किसी भी घटना की सूचना देने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम 24 घण्टें खुला रहेगा।

बैठक के अंत में कलेक्टर ने शांति समिति के माध्यम से जिले के सभी निवासियों से आग्रह किया कि त्योहार का आयोजन समाज को खुशियां प्रदान करता है कोई भी आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिएं कि किसी भी व्यक्ति धर्म अथवा सामुदाय को कोई असुविधा न हो। जिला प्रशासन शांति एवं सौहर्द पूर्ण महौल में त्योहार आयोजन की आपेक्षा करता है। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर पी.के सेन गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार बर्मा, एसडीएम सृजन बर्मा, सीएसपी पीएस परस्ते, थाना प्रभारी विन्ध्य नगर अर्चन द्विवेदी, थाना प्रभारी बैढ़न अशोक सिंह परिहार, यातायात प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी, कार्यपालन यंत्री बी.के चौरसियां, अजीत सिंह बघेल, व्हीपी उपाध्याय सहित समिति के सदस्य डॉ. एनपी मिश्रा, असरफ अली, शहनवाज खान, मुजीब खान, राजाराम केशरी सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

एनएससी के बाद अब एनसीएल के सिंगरौली केंद्रीय अस्पताल में शुरू हुआ नया डायलिसिस सेंटर

मेडिकल सुविधा के क्षेत्र में एनसीएल का सिंगरौली परिक्षेत्र को नई सौगात

सिंगरौली। सिंगरौली परिक्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने मोरवा स्थित केंद्रीय अस्पताल में एक नया डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की है जिसमें 2 मशीनें स्थापित की गईं हैं। बुधवार को, सीएमडी एनसीएल बी. साईराम ने निदेशक (कार्मिक) मनीष कुमार, निदेशक (तकनीकी/संचालन) जितेंद्र मलिक, निदेशक (तकनीकी/ परियोजना और योजना) सुनील प्रसाद सिंह की उपस्थिति में डायलिसिस सेंटर को लोकार्पित किया।इस अवसर पर सीएमएस,एनसीएल डॉ विवेक खरे ,महाप्रबंधक (सिविल) पीके राय, विभागाध्यक्ष, कल्याण राजेश चौधरी, सीएमएस एनएससी डॉ पंकज कुमार, मुख्यालय स्तरीय जेसीसी सदस्यगण, , सिंगरौली केन्द्रीय चिकित्सालय के डॉक्टर, चिकित्साकर्मी और अन्य उपस्थित रहे।केंद्रीय अस्पताल में

स्थापित यह नया डायलिसिस सेंटर सिंगरौली परिक्षेत्र, खासकर मोरवा क्षेत्र और आसपास के गांवों के किडनी रोग के मरीजों को लाभ पहुंचाएगा। डायलिसिस मशीन यूनिट, किडनी के बीमारी से ग्रस्त मरीजों को रक्त शोधन सुविधा प्रदान करने में मदद करती है।एनसीएल के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत (एनएससी) में पहले से ही 8 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। ग़ौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में एनएससी में 1650 से अधिक हेमोडायलिसिस किए गए थे। किडनी की बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनसीएल की यह पहल एनसीएल कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी।एनसीएल अपने तीन अस्पतालों व परियोजनाओं की डिस्पेन्सरी के माध्यम से कर्मियों व हितग्राहियो को बेहतर इलाज मुहैया करवाने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है व चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नवाचारी पहल कर रही है।

संपूर्णता अभियान अंतर्गत जिले में लगाए गए 997 विशेष स्वास्थ्य शिविर

सिंगरौली। सिंगरौली जिले में आकांक्षी जिला एवं जिले के देवसर विकासखंड में आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत लक्षित संकेतकों जैसे गर्भवती महिलाओं का समय पर प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार मिलना, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, हर व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण, स्वस्थ सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड प्रदाय होना, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं आदि को आगामी तीन माह में संतृप्त करने हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान

चलाया जा रहा है जिसका शुभारंभ दिनांक 4 जुलाई 2024 को अटल सामुदायिक भवन बैढ़न में किया गया है। इस अभियान के दौरान लक्षित संकेतको को संतृप्त करने हेतु कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली श्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक विशेष स्वास्थ्य शिविर चलाया गया। जिसके तहत जिले में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक कुल 997 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। जिसमें कुल 1929 गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में पंजीयन एवं जांच तथा 2627 बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण, डायबिटीज़ के 25717 तथा हाइपरटेंशन के 25718 लक्षित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई ।उक्त स्वास्थ्य शिविर नोडल चिकित्सा अधिकारी के देखरेख में संपन्न कराया गया जिसमें सी.एच.ओ, एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग करते हुए विशेष स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाया।

यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालको को विरुद्ध की गई चालानी कार्यवाही

सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता सिंगरौली के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा सिंगरौली, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर पी.एस. परस्ते के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस टीम के द्वारा शहर के चौराहो पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही एवं जागरुकता अभियान चलाया गया।

थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक विद्यावारिधि तिवारी के नेतृत्व में एक सप्ताह के अंदर दिनांक 04-07-2024 से 10-07-2024 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 320 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही कर 1,10,000 रूपये जुर्माना अधिरोपित किए जाने के साथ-साथ जागरुकता अभियान चलाया गया।सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम लगाया जाकर शहर के विभिन्न चौराहे जैसे माजन मोड़, इंदिरा चौक, अंबेडकर चौक, मस्जिद तिराहा, कालेज तिराहा ,अमलोरी तिराहा, जयंत बस पड़ाव, निम्न स्थानों पर यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक जो बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठ कर वाहन चलाना। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग,वाहनों का नम्बर प्लेट

निर्धारित मानक अनुरूप ना होना,वाहनों में बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमति के बिना परिवर्तन या मोडिफिकेशन कराना, दो पहिया वाहनों या बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन साइलेंसर लगाना, शहर के अंदर निर्धारित गति का पालन न करते हुए तेज रफ्तार में वाहन चलाना 8. रेड लाईट जम्प करना साथ ही शहर के अंदर युवा वर्ग द्वारा दो पहिया वाहन चलाते समय तेज रफ्तार एवं स्टंट ड्राइव करते हुए पाए जाना,चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करना उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही के साथ-साथ समझाइए भी दी गई एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा बॉडीवार्म कैमरे की निगरानी में चलानी कार्यवाही की जा रही है बॉडीवार्म कैमरे के माध्यम से चालानी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है

नो पार्किंग एवं सड़क पर खड़े वाहनों पर व्हील लॉक लगाकर की जा रही कार्यवाही । शहर की सड़कों पर नो पार्किंग जोन में वाहन चालकों द्वारा वाहनों को खड़ा कर यातायात अवरोध किया जाता है ऐसे वाहनों पर भी व्हील लॉक लगाकर चालानी कार्रवाई यातायात पुलिस टीम के द्वारा माजन मोड़ से इंदिरा चौक तक मुख्य मार्ग में की जा रही है एवं स्थाई रूप से खड़े वाहनों को लगातार हटवाया जा रहा है सिंगरौली पुलिस जिले वासियों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं से बचें आपका परिवार घर में आपका इंतजार कर रहा है। सिंगरौली पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।

खनहना से चोरी गया ट्रक बरामद, चोर गिरफ्तार

बिहार गई मोरवा पुलिस टीम ने ट्रक किया बरामद

सिंगरौली। बीते दिनों मोरवा थाना क्षेत्र के खनहना में खड़े ट्रक को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में चोरी गया ट्रक बरामद कर लिया, वही इस अपराध में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। जानकारी अनुसार बीते 2 जुलाई को दुल्लापाथर निवासी फरियादी जितेंद्र मौर्य ने मोरवा थाने में तहरीर दर्ज कराई की खनहना में उसके चालक ने उसका ट्रक क्रमांक एचआर 55 एसी 3386 रोड के किनारे खड़ा कर खाना खाने चला गया था। वापस आकर देखा तो ट्रक वहां से गायब था। उसने बताया कि किसी अज्ञात चोर द्वारा ट्रक चोरी करके ले गया है। इस घटना पर मोरवा थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने सिंगरौली पुलिस अधीक्षक के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार पांडे की

मार्गदर्शन में फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 303(2) बीएनएस कायम कर अपराधी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बिहार का रहने वाला है, जिसकी तलाश में एक टीम बिहार राज्य भेजी गई। वहीं तफ्तीश के दौरान पता चला कि ट्रक को हाथीनाला के पास देखा गया है। जिस पर तत्काला टीम रवाना कर आरोपी को ट्रक के साथ धरदबोचा गया। पुलिस की पूछ?ताछ में आरोपी अखिलेश उराव उर्फ भीम पिता राजेश उराव साकिन रोहतक बिहार हालमुकाम खनहना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बुधवार को मोरवा पुलिस ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चालक ने पूछताछ में इस चोरी में अन्य लोगो के साथ होता भी बताया है, जिसे पकड़ने की कवायत जारी है।उक्त कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक सुमत, अर्जुन सिंह, आरक्षक नीरज यादव, अमित द्विवेदी शामिल थे।

एनसीएल ने सीएसआर तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किया एमओयू

सिंगरौली। बुधवार को भारत सरकार की संकल्प योजना के अंर्तगत कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने जिला प्रशासन, सिंगरौली के साथ एक एमओयू किया है ।नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक, जयंत क्षेत्र राजीव कुमार एवं जिला प्रशासन सिंगरौली की ओर से प्राचार्य शासकीय औद्यौगिक संस्थान, सिंगरौली मकर ध्वज चौहान ने उक्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार एनसीएल जयंत के निगमित सामाजिक दायित्व के मद से रू 9.20 लाख की वित्तीय सहायता की जाएगी जिसके माध्यम से संकल्प योजना के तहत सिंगरौली जिले के 510 युवाओं को भारी वाहनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान जयंत क्षेत्र के स्टॉफ अधिकारी (कार्मिक) पी के त्रिपाठी, नोडल अधिकारी (सीएसआर) साजिद नसीम एवं आईटीआई, सिंगरौली के टीपीओ ओम प्रकाश उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने माइनिंग कंपनियों की एक्सप्लोसिव प्रक्रियो के समय एवं तीव्रता पर ली समीक्षा बैठक

विस्फोटक प्रक्रिया में करे सुधार आमजन को न हो परेशानी : चन्द्रशेखर

सिंगरौली। माइनिंग कंपनियों द्वारा किए जा रहे ब्लास्टिंग प्रक्रिया के समय को आम जनता के सहूलियत के हिसाब से रखा जाने के आशय से कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में विभिन्न उद्योगिक कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई।कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित कंम्पनियों को प्रतिनिधियों को निर्देश दिए की ब्लास्टिंग प्रक्रिया में सुधार लाए साथ ही यह सुनिश्चित करे कि ब्लास्टिग के दौरान आमजन कोई परेशानी न हो। ब्लास्टिंग के समय की जानकारी से आम जनों को भी अवगत करायें।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने माइनिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों से उनके ब्लास्टिंग के समय की जानकारी ली तथा ब्लास्टिंग के कंपन से प्रभावित रहवासी क्षेत्रों की भी जानकरी ली। जानकारी उपरांत कलेक्टर ने सभी माइनिंग कंपनियों को संबोधित करते हुए कहा की ब्लास्टिंग गतिविधियों से माइंस के पास रहवासी क्षेत्रों में आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता इससे उनके आवासों को भी नुकसान पहुंचता है । इसके अलावा वर्तमान के ब्लास्टिंग का जो समय है उससे स्कूली बच्चों भी प्रभावित हो रहे है । उन्होंने समस्त माइनिंग कंपनियों को निर्देश दिए की वह अपने गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों का सर्वे करे और यह सुनिश्चित करले की विस्फोटक प्रक्रिया से आम जन परेशान न हो।। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ब्लास्ट टाइमिंग की सूचना जगह जगह चस्पा कराये। साथ ही इस जानकारी को न्यूज पेपर , सोशल मीडिया सहित कंपनी वेबसाइट , एनाउसमेंट के मध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा की कंम्पनियां अपने विस्फोटको क्षमता और उसके होने वाले कंपन को मान्य दर में सीमित रखे। जहा पर आबादी ज्यादा है वह पर ब्लास्टिंग का समय जनता की सहूलियत के हिसाब से रखा जाए तथा इसकी सूचना रहवासियों सहित सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम को भी दिया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्त द्वारा कंपनियों को आमजनों से नियमित संचार और बातचीत करने के निर्देश दिए ताकि जनजागरण हो सके। उन्होंने ने कहा भविष्य में आम जनों को परेशानी न होने इसके लिए कंम्पनियां अपने विस्फोटक प्रक्रिया के समय सुधार करना होगा ।

बलियरी बना रेत माफियाओ का ठिकाना, सैकड़ो ट्रैक्टर रेत डम्प

खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन रेत माफियाओं के खिलाफ नहीं कर रहा कार्रवाई, उठ रहे सवाल

सिंगरौली। बैढ़न थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 38 तुलसी वार्ड के बलियरी में एक बार फिर से रेत माफिया रेण व मयार नदी का सीना छल्ली कर रहे हैं रेत का भंडारण कर बरसात में बिक्री करने के लिए कर रहे हैं साथ ही रेत निकासी करते हुए रेत इकट्ठा कर रहे है वो भी जिला प्रशासन के नाक के नीचे। कार्यवाही नही होना कई सवाल खड़े हो रहे है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैढ़न मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर वार्ड क्रमांक 38 के बलियरी में रेत माफिया एक बार फिर से सक्रिय हुए है जहां पर सैकड़ो ट्रैक्टर अवैध रेत का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है ताकि बरसात में अवैध रेत को बिक्री कर मोटी रकम

कमाई जा सके। बता दे कि पिछले महीने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला व पुलिस अधीक्षक सिंगरौली निवेदिता गुप्ता के मार्गदर्शन में खनिज अधिकारी एके राय द्वारा अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए बलियरी में जगह-जगह अवैध रेत भंडारण पर छापा मार कार्यवाही में लाखों रुपए का अवैध रेत जप्त किया गया था। कुछ दिन तक रेत माफिया अंडर ग्राउंड हो गए थे, अब जहां मामला ठंडा हो गया है और जिला प्रशासन शिथिल हो गया है, वही एक बार फिर से रेत माफिया अपने काम को अंजाम देने के लिए बलियरी के रेण व मयार नदी में सक्रिय हो गए और जितना जिला प्रशासन ने रेत जप्त किया था उससे तीन गुना रेत इकट्ठा कर लिए हैं। बताया जाता है कि रात के अंधेरे से दिन के उजाले तक रेत माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से रेत इकट्ठा किया जा रहा है। रेत माफियाओं द्वारा 2500 रुपये ट्रैक्टर अवैध रेत को विक्रय किया जाता है। इस प्रकार लाखों रुपए का रेत रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक रेत माफिया द्वारा पार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि रेत माफियाओं द्वारा बारिश में बिक्री करने के लिए बलियरी के मैदान व अपने और दूसरों के घरो के आगे-पीछे की तरफ जगह-जगह लगभग 1000 ट्रैक्टर अवैध रेत को नदी से निकाल के किया गया है इकट्ठा, ताकि बरसात में बिक्री कर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके, ऐसे में 1000 ट्रैक्टर रेत को यदि 2500 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो 25,00,000 लाख रुपये का रेत इकट्ठा किया गया हैं।

बैढ़न पुलिस पर भी उठ रहे हैं सवालिया निशान

अब ऐसे में देखा जाए तो पुलिस द्वारा बैढ़न थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बलियरी में एक भी ट्रैक्टर पर कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं बैढ़न पुलिस पर भी निशानियां सवाल खड़ा करता है। वही बलियरी के वार्ड वार्डवासियो का कहना है कि इन अवैध रेत कारोबारियो की ट्रैक्टर इतनी रफ्तार से चलती है कि कोई हादसा होने का खतरा बना रहता है और रात भर यह ट्रैक्टर फर्राटा भरते हैं, इन ट्रैक्टरों की चलने की गड़गड़ाहट से हम रातभर सो भी नहीं पाते।एक बार फिर से बलियरी के वार्डवासी जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की ओर निहारते दिख रहे हैं, जहां वार्डवासी आस लगाए बैठे हैं कि एक बार फिर इन रेत माफिया पर कार्रवाई की जाए और जो लाखों रुपए का रेत इकट्ठा किया गया है उसे जप्त किया जाए।

अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें : कमिश्नर

सीधी

सीधी जिले के प्रवास के दौरान कमिश्नर रीवा संभाग बी.एस. जामोद ने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ सहजता से पहुंचाएं। ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक भ्रमण करें तथा ग्रामवासियों से अपनत्व के भाव से मिलें। उनकी समस्याओं को जाने तथा तत्परता से उनका निराकरण सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने निर्देशित किया कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ सहजता से मिले तथा वह विकास की मुख्य धारा से जुड़े।

कमिश्नर श्री जामोद ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि सभी शासकीय विद्यालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करायें। विद्यालयों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थित समय से

हो। लक्ष्यानुसार विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। ऐसे विद्यार्थी जो समय पर विद्यालय नहीं आते हैं उनके अभिभ्ज्ञावकों से संपर्क कर उन्हें समय पर विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करें। कमिश्नर ने गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने पर विशेष जोर दिया। कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा से ही विकास को गति मिलेगी। शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपना योगदान दें। गत वर्ष जिन विद्यालयों का परिणाम खराब रहा है उन पर विशेष ध्यान दें। कमिश्नर ने जिले के सभी विद्यालयों में पुस्तक वितरण का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।

कमिश्नर ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन विभाग एक टीम के रूप में कार्य करें। जिला स्तर पर उक्त विभागों के अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करायें जिनमें उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी हो। कृषकों की आय में वृद्धि के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है। कमिश्नर ने ऐरा प्रथा रोकने के लिए पशुपालन विभाग को जनजागरण अभियान चालने के निर्देश दिए हैं। जिसमें राजस्व विभाग तथा पंचायत विभाग सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होने पशुपालन के लिए किसान भाइयों को प्रेरित करने, बर्मी कम्पोस्ट के लिए मुहिम चलाने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी किसानों के बीच में अधिक से अधिक समय बिताएं, किसानों को नवीन तकनीकी की जानकारी दें तथा उन्नत कृषि को बढ़ावा दें। कमिश्नर ने जिले के सभी तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन एवं उद्यानिकी के लिए क्लस्टर बेस्ट एप्रोच अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री प्रायमरी शिक्षा की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र में नजदीकी विद्यालय के शिक्षक सप्ताह में एक दिन 3 घंटे का समय व्यतीत करेंगे तथा 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। पोषण के स्तर में सुधार के लिए कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। जिले में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया गया है।

कमिश्नर ने सभी निर्माण एजेन्सियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा समय-सीमा को ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सभी मार्गों के मरम्मतीकरण के कार्यों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने लक्ष्यानुसार सभी बैंको में प्रकरण प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। बैंक उनका परीक्षण कर लें तथा कमियों को हितग्राहियों से संपर्क कर आवश्यक सुधार करा लें। कमिश्नर ने दिसम्बर के पूर्व शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। लंबित सीमांकन के निराकरण के लिए जिले में प्रत्येक शनिवार को सीमांकन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विगत दो सप्ताह में 18 सौ से अधिक सीमांकन किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए जिले में शून्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत गत एक माह में 2 हजार से अधिक पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल रूम संचालित है जो लगातार हितग्राहियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए क्रिक रिस्पांस टीम गठित की गई है। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि जिले की पूरी टीम संवेदनशीलता के साथ शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगी। कमिश्नर ने जिले के नवाचारों की सराहना करते हुए लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कहा है।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संतोष त्रिपाठी, उपायुक्त डीएस सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कमिश्नर ने गोरियरा जलाशय में केज कल्चर इकाई का निरीक्षण किया

सीधी। कमिश्नर रीवा संभाग बी.एस. जामोद द्वारा गोरियरा जलाशय में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत स्थापित केज कल्चर इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर श्री जामोद द्वारा हितग्राहियों से चर्चा की गई । हितग्राही द्वारा विस्तार से केज में किये जा रहे मत्स्यपालन की गतिविधियों से अवगत कराया गया। कमिश्नर द्वारा गोरियरा जलाशय में स्थापित केज कल्चर इकाई में किये जा रहे मत्स्यपालन की गतिविधियों की सराहना की गई। कमिश्नर ने सहायक संचालक मत्स्योद्योग सीधी को निर्देशित किया कि गोरियरा जलाशय में केज कल्चर इकाई का विस्तार करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र संचालनालय मत्स्योद्योग म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया जाये। इस अवसर पर उनके साथ कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपायुक्त डीएस सिंह, सहायक संचालक मत्स्योद्योग दीपक शुक्ला सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कमिश्नर ने किया अमृत सरोवर एवं चेक डैम का निरीक्षण

सीधी। सीधी प्रवास के दौरान कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद द्वारा ग्राम पंचायत खिरखोरी के छपरहिया टोला में अमृत सरोवर तथा रेवनार नदी में बने चेक डैम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने हितग्राहियों अमृत लाल कोल एवं अन्य को अमृत सरोवर को मत्स्य पालन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया। कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को उक्त कार्य में हितग्राहियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संतोष त्रिपाठी, उपायुक्त डीएस सिंह, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी अशोक तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

चोरों ने ताला तोड़कर 8 लाख रुपए का सामान किया पार

सिंगरौली। सरई थाना की निगरी पुलिस चौकी क्षेत्र ग्राम पंचायत निगरी में इन दिनों चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। अरसे से निगरी जेपी कम्पनी में कबाड़ चोरी का सिलसिला आये दिन चलता ही रहता है किन्तु इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शाम ढलते ही घरों व दुकानों में चोरियों को अंजाम देने लगे हैं। एक दुकानदार राकेश कुमार जायसवाल ने पुलिस चौकी निगरी को लिखित सूचना देकर अवगत कराया है कि निगरी शिव चौक पर उसकी रेडीमेड कपड़े की दुकान है। यह दुकान किराए के मकान पर है वह 15 दिनों के लिए बाहर काम से गया था।

उपमुख्यमंत्री से मिले सांसद, चिकित्सा व्यवस्था में होगा क्रांतिकारी परिवर्तन

सीधी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ राजेश मिश्रा अपने भोपाल प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से मिलकर सीधी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा की।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि डॉ राजेश मिश्रा स्वयं डॉक्टर होने के नाते एवं चिकित्सा क्षेत्र का व्यापक अनुभव होने के नाते उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ला से सीधी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की अपार जन संभावनाओं पर व्यापक चर्चा और विमर्श किया। इसके पश्चात सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि अति शीघ्र सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र

सीधी, सिंगरौली और व्यौहारी विधानसभा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। चिकित्सकों की कमी, मेडिकल कॉलेज एवं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ की नियमित नियुक्ति चर्चा के प्रमुख बिंदु रहे।

उपमुख्यमंत्री डॉ राजेंद्र शुक्ल ने सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को लोकसभा में शानदार विजय श्री अर्जित करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी और सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

सीधी प्रवास के दौरान डॉ राजेश मिश्रा ने अचानक केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर विद्यालय में चल रही पाठ्य और पाठ्येत्तर गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान सांसद डॉक्टर मिश्रा ने विभिन्न क्लासों में जाकर छात्र-छात्राओं से रूबरू हुए और उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं सांसद डॉ राजेश मिश्रा को अपने बीच पाकर अत्यधिक हर्षित दिखे वहीं सांसद डॉक्टर मिश्रा ने भी छात्रों को अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया।

सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा अपने सीधी प्रवास के दौरान स्थानीय वैष्णवी गार्डन सांसद कार्यालय में शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अंचल से आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें आश्वासन भी दिया। कुछ समस्याओं का निराकरण त्वरित किया गया, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में अपार उत्साह देखा गया।

महिला सरपंचों ने कहा शासन की योजनाओं की मिल रही जानकारी

महिला सरपंचों का क्षमता वर्धन करने दूसरे दिन भी जिला पंचायत में आयोजित हुआ एक दिवसीय प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण

सिंगरौली। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली गजेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला के जनपद पंचायत देवसर, चितरंगी एवं बैढ़न अंतर्गत ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित महिला सरपंचों का क्षमता वर्धन करने हेतु जिला पंचायत में प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में महिला सरपंचों को पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , ग्राम सभा , समितियों के मुख्य कार्य एवं

शक्तियां तथा उत्तरदायित्व, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विभागीय पोर्टल, जीपीडीपी आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। एक दिवसीय जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण मैं कल 9 जुलाई को बैढ़न जनपद की 57 महिला सरपंचों ने भाग लिया था तथा आज 10 जुलाई को देवसर जनपद की 42 महिला सरपंचों ने भाग लिया तथा प्रशिक्षण के तीसरे एवं आखिरी दिन 11 जुलाई को चितरंगी जनपद की 66 महिला सरपंच भाग लेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला सरपंचों का कहना है कि इस प्रशिक्षण से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जिससे ये शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में और अधिक सक्षम होगी।

मार्ग परिवर्तित के संबंध में

शहडोल। सहायक मंडल अभियंता रेल्वे शहडोल ने जानकारी दी है कि रेलवे समपार क्र बीके-72, पुरानी बस्ती शहडोल को सड़क यातायात हेतु बन्द किया गया है। सड़क यातायात हेतु नव-निर्मित एलएचएस (सीमित उंचाई का उप-रास्ता) प्रारंभ कर दिया गया है। सड़क यातायात हेतु रेलवे कि 3 लाइन की ओर एक पुरानी निर्मित, प्रचलित. सड़क एवं दूसरी नई निर्मित सड़क को खोला गया है।

शहडोल जिले में एक पेड मां के नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए जगा रहा अलख

शहडोल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गयी है। शहडोल जिले में यह अभियान अब जन-जन का अपना अभियान बन चुका है। प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह अभियान अलख जगा रहा है। हर कोई अपने माँ के लिए पेड़ लगाकर इस अभियान के प्रति अपनी सजगता दिखा रहा है। पेड़-पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं। बल्कि विभिन्न प्रकार के फल-फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं। घर के आसपास पौधरोपण करने से गर्मी, भू क्षरण, धूल आदि की समस्या से बच सकते हैं। इसी तारतम्य में शहडोल जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टर श्री तरूण भटनागर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रचलन में है। इस अभियान में जिले के नागरिक बढ़ चढकर सहभागिता निभा रहे हैं और अपनी माँ के नाम पर और प्रकृति के आंचल को हरा-भरा रखने के लिए पौधरोपण कर रहे हैं तथा रोपे गए पौधों को जीवित रखने का संकल्प ले रहे हैं। इस अभियान के तहत पीएचई कार्यालय के परिसर, कोआपरेटिव कार्यालय के परिसर, जनपद पंचायत बुढार ग्राम पंचायत बिरौडी में लोगों ने पौधरोपण किया तथा पौधों की सुरक्षा और उन्हें जीवित रखने का संकल्प लिया।

जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर 27 जुलाई को

शहडोल। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण प्रज्ञा मरावी ने जानकारी दी है कि भारत सरकार की एडिप योजनान्तर्गत जिले के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग (कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, कैलिपर्स, केरेक्टिव सूज) सहायक उपकरण (ट्रायसायकिल, मोटराइज्ड ट्रायसायकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, वाकिंग स्टिक, कान की मशीन) आकलन एवं चिन्हांकन उपरांत प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन 27 जुलाई 2024 को गाँधी स्टेडियम नगर पालिका शहडोल में किया जाएगा। दिव्यांग शिविर में यू.डी.आई.डी. कार्ड (अनिवार्य रूप से) 40 प्रतिशत या अधिक, आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड एवं 2 पासपोर्ट फोटो दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

कमिश्नर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई

शहडोल। कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आज साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में संयुक्त आयुक्त विकास श्री मगन सिंह कनेश ने शहडोल संभाग के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी तथा निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत बेलिया बड़ी जनपद पंचायत अनूपपुर निवसी पुष्पा मिश्रा ने आवेदन देकर बताया कि मेरे पति की मृत्यु 3 नवम्बर 2023 को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में हो गई थी जिसमें संबल कार्ड के तहत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिया गया था किन्तु अभी तक संबल कार्ड के तहत सहायता राशि प्रदान नही की गई है तथा सरपंच, सचिव एवं सीईओ द्वारा 25 हजार रूपये की मांग की जा रही है। उनका कहना था कि मुझे संबल कार्ड के तहत सहायता राशि प्रदान करवाने का कष्ट करें। जिस पर संयुक्त आयुक्त विकास ने संबंधित विभाग के अधिकारी की ओर आवेदन प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में शहडोल जिले के ग्राम पंचायत बरकोडा निवासी मंगल जयसवाल ने आवेदन देकर बताया कि मैं ग्राम पंचायत बरकोडा मे मजदुर का कार्य करता हूँ मै खेत तालाब निर्माण कार्य रामसजीवन नट के खेत मे दिनांक 27/10/2022 से 19/01/2023 तक कार्य किया था। जिसका कुल कार्य 40 दिवस था एवं सोखता गडढा (शोकपिट) निर्माण आंगनवाडी केंद्र/प्राथमिक शाला बरई में दिनांक 06/04/2023 से 15/04/2023 तक कार्य किया था। शोकपिट मे कुल कार्य 8 दिवस था। ग्राम पंचायत बरकोडा सचिव श्री रामसिरोमणी शर्मा ग्राम पंचायत बरकोडा के खाता मे राशि होने के बावजूद मजदुर का मस्टर रोल नही निकाल रहा है और न ही ग्राम पंचायत के खाता से मजदुरी भुगतान कर रहा है। एक वर्ष से ऊपर समय हो गया है। मजदुरी मांगने पर सचिव श्री रामसिरोमणी शर्मा द्वारा ध्यान नही दिया जा रहा है। जीवन यापन करने में दिक्कत का सामना करना पड रहा है। उनका कहना था कि मेरा मजदूरी का भुगतान कराया जाए। जिस पर संयुक्त आयुक्त विकास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहपारू की ओर आवेदन प्रेषित कर मजदूरी का भुगतान कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनसुनवाई में शहडोल संभाग के दूर-दराज से आए अन्य लोंगो की भी सुनवाई की गई तथा निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए।

यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वाले स्कूल वाहनो के विरुद्ध की गई कार्यवाही

सिंगरौली। श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भापुसे) पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देशन में एवं शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिगरौली, एवं पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर के मार्गदर्शन में स्कूल वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही की गई। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, एवं यातायात नियमों की जागरुकता हेतु लगातार यातायात प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 02.07.2024 को स्कूली बच्चों के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु यातायात पुलिस द्वारा ग्रामीण एव शहरी क्षेत्र में अलग-अलग टीमें लगाई जाकर स्कूलो से अनुबंधित वाहनो के विरूद्ध

शासन द्वारा स्कूल बसो हेतु जारी दिशा-निर्देश का पालन नही करने के कारण 34 स्कूल वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही कर 21,000 रूपये संमन शुल्क जमा कराया गया है।स्कूल वाहनो वाहनो द्वारा स्कूली बच्चो के परिवहन एवं स्कूल बसो हेतु निर्धारित की गई गाइड लाइन एवं निर्देशो का पालन नहीं किए जाने पर अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, स्कूली वाहनो पर उक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। सिंगरौली पुलिस समस्त अशासकीय एवं शासकीय स्कूल प्रबंधन एवं बस आपरेटरो से अपील करती है, कि स्कूली बच्चो के परिवहन संबंधी शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशो के अनुरूप वाहनो के दस्तावेज एंव स्कूली बच्चो के सुरिक्षत परिवहन हेतु समस्त दिशा-निर्देशो का पालन करे। इस सराहनीय कार्यवाही मे उनि अभिषेक पाण्डेय, सउनि सुरेश शुक्ला, सउनि हॉमिद खॉन, प्रआर पुष्पेन्द्र, प्रआर उमेश बागरी, प्रआर नंदकिशोर, आर प्रवेश तिवारी एंव अन्य समस्त यातायात स्टॉप का योगदान रहा।

संपादकीय

बिहार में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े ब्रिज

बिहार में मानसून की शुरुआत में ही एक के बाद एक पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार हरकत में आई और जल संसाधन तथा ग्रामीण कार्य विभाग के पंद्रह अभियंताओं को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि राज्य में बीते कुछ दिनों के भीतर विभिन्न इलाकों में नए-पुराने दस पुल ढहने की खबर आ चुकी है। हैरानी की बात है कि ध्वस्त पुलों में कुछ निर्माणाधीन थे। सवाल है कि बिहार की मौजूदा सरकार अपने जिस सुशासन के दावे अक्सर करती रहती है, उसमें लगातार पुलों के ढहने को कैसे देखा जाए। कुछ वर्ष पहले बने या फिर निर्माणाधीन पुल अगर इस तरह गिर गए, तो इसके पीछे घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के अलावा और क्या वजह हो सकती है विडंबना है कि जहां पुलों के लगातार ढहने की जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाती, बाकी पुलों के रखरखाव और नए पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार खत्म करके उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती, वहीं इस मसले पर नाहक सियासी बयानबाजियां शुरू हो गईं। ढह गए पुलों की जिम्मेदारी पर सियासत क्या इस समस्या का समाधान है दरअसल, भ्रष्टाचार के ये पुल सुशासन के दावों की हकीकत बता रहे हैं। लगातार पुलों के गिरने की घटनाओं पर कठघरे में घिरी सरकार का कहना है कि उसके अधीन निर्मित जो पुल गिरे हैं, उनका जिम्मा संभालने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सवाल है कि जब इन पुलों का निर्माण हो रहा था तो संबंधित विभाग ने इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई दूसरा ठेकेदार पुल के निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा पुलों के गिरने की घटनाओं को लेकर गठित जांच समिति ने अपनी शुरुआती रपट में कहा है कि विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्य की निगरानी करने और बाद में पुलों की देखरेख में लापरवाही बरती। इसी रपट के आधार पर पंद्रह अभियंताओं को निलंबित किया गया है। मगर क्या सिर्फ संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर देने से इस की समस्या का समाधान हो जाएगा भ्रष्टाचार के जिस जाल की वजह से ऐसी समस्याएं पैदा होती।

भारत में वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ हद्द तक वामपंथी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया था। परंतु, वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खंडकाल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना रहे थे, ने भी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप हो इस वर्ष का बजट

(प्रह्लाद सबनानी)

भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्णकालिक बजट माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय संसद में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के लगभग समस्त देशों में पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। परंतु, हाल ही के वर्षों में पूंजीवादी नीतियों के अनुसरण के कारण, विशेष रूप से विकसित देशों को, आर्थिक क्षेत्र में बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह देश इन समस्याओं का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नियंत्रण से बाहर होती मुद्रा स्फीति की दर, लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, प्रौढ़ नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार के खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, बजट में वित्तीय घाटे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका हल विकसित देश बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं एवं इन देशों का सामाजिक तानाबाना भी छिन्नभिन्न हो गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि व्यक्तिवाद हावी रहता है अतः स्थानीय समाज में विभिन्न परिवारों के बीच आपसी रिश्ते केवल आर्थिक कारणों के चलते ही टिक पाते हैं अन्यथा शायद विभिन्न परिवार एक दूसरे से रिश्तों को आगे बढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। कई विकसित देशों में तो पति-पत्नि के बीच तलाक की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। अमेरिका में तो यहां तक कहा जाता है कि 60 प्रतिशत बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं होती है एवं केवल माता को ही अपने बच्चे का लालन-पालन करना होता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है एवं यह बच्चे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समाज में हिंसा की दर बढ़ रही है तथा वहां की जेलों में कैदियों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। इन देशों के नागरिक अब भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं एवं उन्हें उम्मीद है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का हल भारतीय सनातन संस्कृति में से ही निकलेगा। अतः इन देशों के नागरिक अब भारतीय सनातन संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं।

भारत में वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ हद् तक वामपंथी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया था। परंतु, वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खंडकाल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना रहे थे, ने भी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है।

भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक

पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। उस समय पर भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया जाता था। मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण का बोझ, वित्तीय घाटा, बुजुर्गों को समाज पर बोझ समझना, बच्चों का हिंसक होना, सामाजिक तानाबाना छिन्नभिन्न होना आदि प्रकार की समस्याएं नहीं पाई जाती थीं। समाज में समस्त नागरिक आपस में भाईचारे का निर्वहन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे।

प्राचीन काल में भारत के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते मुद्रा स्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहां खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। माननीय वित्तमंत्री महोदय को भी देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णत असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर वांछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अर्थात आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे मुद्रा स्फीति तो कम होगी ही परंतु साथ ही अर्थव्यवस्था में विकास की दर भी और तेज होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ते रहने से विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। परंतु यदि वस्तुओं की मांग में कमी करते हुए मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास होंगे तो उत्पादों की मांग में कमी होने के चलते उत्पादों का निर्माण कम होने लगेगा, विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां कम होंगी एवं देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। मांग में कमी करने के प्रयास सम्बंधी सोच ही अमानवीय है।

इसी प्रकार, प्राचीन भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे, इन कृषि उत्पादों के साथ ही इन कुटीर एवं लघु उद्योगों में निर्मित उत्पाद भी बेचे जाते थे। अतः ग्रामीण इलाकों से शहरों की पलायन नहीं होता था तथा नागरिकों को रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध हो जाते थे। आज की परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित हो सकें। जनता पर करों के बोझ को कम करने के सम्बंध में भी विचार होना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों में कर सम्बंधी नीति का वर्णन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य को जनता पर करों का बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना एक मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है। यदि किसी देश में अधिक से अधिक आर्थिक व्यवहार औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था का चक्र भी तेज गति से घूम रहा है तो ऐसी स्थिति में करों के संग्रहण में भी वृद्धि दर्ज होती है। अतः कई बार करों की दरों में कमी किए जाने के बावजूद कर संग्रहण अधिक राशि का होने लगता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि माननीया वित्त मंत्री जी के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के रूप में एक अच्छा मौका है कि भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप आर्थिक नीतियों को लागू कर पूरे विश्व को पूर्व में अति सफल रहे भारतीय आर्थिक दर्शन के सम्बंध में संदेश दिया जा सकता है।

(लेखक सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

आखिर इन कंगारू अदालतों को संरक्षण कौन दे रहा

(प्रभाकर मणि तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर सब-डिवीजन के चोपड़ा का वायरल वीडियो तेजी से फली-फूली इसी अदालत की ताकत का सुबूत है। यह घटना न तो पहली है और न ही आखिरी। अकेले चोपड़ा इलाके में ही हर महीने औसतन तीन से चार ऐसी सभाएं आयोजित होती रही हैं। उत्तर और दक्षिण बंगाल का कोई भी इलाका त्वरित न्याय की इस असांविधानिक परंपरा से अछूता नहीं है। ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही जज और जल्लाद, दोनों बन जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में 13 साल पहले निजाम बदल गया था। मगर इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत नहीं बदली। पूरे देश में भले कानून और सरकार का शासन चलता हो, मगर पश्चिम बंगालके ग्रामीण इलाकों में कंगारू अदालतों का हुक्म सबसे ऊपर है। स्थानीय भाषा में इसे 'सालिसी सभा' कहा जाता है। खौफ इतना कि इसके फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अदालत खुद फैसले करती है और खुद ही मौके पर सजा भी दे देती है।

उत्तर दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर सब-डिवीजन के चोपड़ा का वायरल वीडियो तेजी से फली-फूली इसी अदालत की ताकत का सुबूत है। यह घटना न तो पहली है और न ही आखिरी। अकेले चोपड़ा इलाके में ही हर महीने औसतन तीन से चार ऐसी सभाएं आयोजित होती रही हैं। उत्तर और दक्षिण बंगाल का कोई भी इलाका त्वरित न्याय की इस असांविधानिक परंपरा से अछूता नहीं है। ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही जज और जल्लाद, दोनों बन जाते हैं। चोपड़ा की वह घटना भी सामने न आती, अगर दो नौजवानों ने अपनी जान हथेली पर लेकर उसका वीडियो न बनाया और वायरल किया होता। अब सभा के आयोजक उन दोनों युवकों की तलाश कर रहे हैं और उन पर 50-50 हजार रुपये के जुर्माने भी लगाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में इन सभाओं का आयोजन करने वाले दबंगों का इस कदर आतंक है कि ऐसी इक्का-दुक्का घटनाएं ही सामने आ पाती हैं।

इस घटना के बाद स्थानीय तृणमूल विधायक हमीदुल को कारण बताओ नोटिस जारी करने और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से चेतावनी देने के बावजूद राज्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पूर्व बर्द्धमान जिले के एक ताजा मामले में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने एक बुजुर्ग दंपति की

इसलिए घर में घुसकर पिटाई कर दी, क्योंकि वे दोनों ऐसी ही एक सभा में बुलाए जाने के बावजूद हाजिर नहीं हुए थे। इन सभाओं में अवैध संबंधों, विजातीय प्रेम विवाह, खेत की मेड़ काटने और संपत्ति-विवाद समेत किसी भी स्थानीय विवाद की स्थिति में फौरन फैसला सुनाया जाता है। ये फैसले भी अजीबोगरीब होते हैं। जैसे, कथित दोषियों से जुर्माना वसूलने के अलावा कभी किसी अवैध रिश्ते की कथित दोषी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का आदेश दिया जाता है, तो कभी पत्नी की कथित पिटाई करने वाले अभियुक्त को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है।

राज्य में वाम मोर्चे की सरकार के जमाने से ऐसी अदालतें आयोजित होती रही हैं। राजनीतिक दल भले ही इनकार करें, पर ऐसी तमाम कंगारू अदालतों को स्थानीय राजनेताओं का संरक्षण हासिल होता है। यही वजह है कि इन अदालतों के गैर-कानूनी फैसलों के बावजूद कभी किसी को कड़ी सजा नहीं मिल पाती। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था, मगर इनका जलवा कम नहीं हुआ। इन कंगारू अदालतों का राज्य की राजनीति से गहरा संबंध है। साल 2004 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने इन सालिसी अदालतों को 'वेस्ट बंगाल ब्लॉक लेवल प्री-लिटिगेशन कौंसिलेशन बोर्ड बिल', यानी सालिसी विधेयक के जरिये इनको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया था। इसके तहत छोटे विवादों के निपटारे के लिए राज्य के हर ब्लॉक में कौंसिलेशन बोर्डों का गठन किया जाना था। लेकिन विपक्षी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जबरदस्त विरोध की वजह से सरकार वह विधेयक विधानसभा में पेश नहीं कर सकी।

बहरहाल, राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस-प्रशासन के लोग इसमें कोई दखल देने से बचते हैं। यदि कोई बड़ी घटना घट गई, तो दो-चार लोगों को गिरफ्तार कर मामले की लीपापोती के प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। मौत या हत्या के ज्यादातर मामलों को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। इन कंगारू अदालतों के फैसले अक्सर बर्बर सामंती दौर की यादें ताजा करा जाते हैं। कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझने के बजाय लोग आपसी विवादों को सुलझाने के लिए इन सालिसी सभाओं को तरजीह देते हैं। मगर यदि 21वीं सदी में ऐसी अदालतें इतनी प्रभावी हैं, तो यह समाज और तंत्र के माथे पर एक बदनुमा धब्बा है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वर्ग पहेली 5427

1	2	3	■	4		5	6
7			■		■	8	
	■	9			10	■	■
11	12		■	13			14
15		■	16			■	
17		18	■		■	19	
	■	20		■	21		
■	22		■	23			■

संकेतः बाएं से दाएं
1. 25 अगस्त 1957 को इस देश की सरकार ने देश में घोषित आपातकाल के 30 वर्ष बाद वापस लिया (3)
4. दोनों हाथों से तीर चला लेने के कारण अर्जुन को एक नाम (4)
7. अमानत में खयानत, मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कृति (3)
8. हृदय, चित्त, चालीस सेर के बराबर की एक तौल (2)
9. प्रसन्न होना, रोमांचित होना (4)
11. उर्दू या फारसी में गजलें लिखने, बोलने वाला (3)
13. सिपाही, सैनिक (3)
15. दो की संख्या, निग्रह (2)
16. सीखने में प्रवृत्त करना, प्रशिक्षित करना (3)
17. सर्दी-जुकाम (उर्दू)(3)
19. उत्तरप्रदेश की पूर्व महिला मुख्यमंत्री (सिर्फ आरंभिक नाम)(2)
20. आकाश से गिरने वाला बिजली (2)
21. जो वास्तविकता से परे हो (3)
22. पवित्र, मंगलकारक, शुभ (2)
23. किसी धार्मिक विषय में धर्मशास्त्र वेत्ता का लिखित आदेश (उर्दू)(3)

ऊपर से नीचे
1. किसीशुभ कार्य के आरंभ में किया गया श्रीगणेश को नमन (7)
2. आधार से समकोण बनाती हुई ऊपर जाने वाली रेखा (2)
3. उत्तरप्रदेश का गंगा तट पर बसा यह नगर चर्मोद्योग के कारण भी प्रसिद्ध है (4)
4. दंड देना, शिक्षा या नसीहत देना (6)
5. गाए जाने वाले वेदमंत्र (2)
6. यह विश्व का प्रथम देश है जिसमें मुद्रा का प्रचलन किया (2)
10. मापना (3)
12. जुड़वा, अश्विनी कुमार (3)
14. आम दरपत, आने-जाने का साधन (4)
18. सलोनापन, स्वभाव की उत्तमता, नमकपन (3)
19. सुपर स्टार सलमान खान क्की पैतृक भूमि मध्यप्रदेश के इस अंचल में स्थित है (3)
21. दुर्दशा, दुर्गति (2)

वर्ग पहेली 5426 का हल

रा	ज	गु	रू	■	भू	त	ल
म	■	बा	त	ची	त	■	ति
च	तु	र	■	फ	■	ना	का
रि	■	■	शा	मि	या	ना	■
त	ला	शी	■	नि	■	ना	ती
मा	त	■	ड	रट	र	■	ई
न	■	प्र	का	र	■	मा	दा
स	ख्ती	■	र	■	स	ह	ज

उ.प्र. भाजपा में क्यों नहीं उभर रही है दलित लीडरशिप

(अजय कुमार)

बीजेपी आलाकमान ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाये हैं उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम से सीख लेते हुए भाजपा ने दलितों में नए सिरे से पैठ बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार व संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जो झटका मिला है, उससे बीजेपी आलाकमान अभी तक उबर नहीं पाया है। हार की कई स्तरों पर लगातार समीक्षा हो रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की हार और वोट प्रतिशत में गिरावट के लिये फिलहाल कई छोटे-छोटे के अलावा दो-तीन बढ़े कारण नजर आ रहे हैं। इसमें प्रत्याशियों के प्रति जनता की नाराजगी के अलावा ओबीसी और दलित वोट बैंक के खिसकने को सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है। इसी के चलते पार्टी के सजातीय मंत्रियों और पदाधिकारियों की लगाम कसने के साथ अब इस वोट बैंक को वापस भाजपा की तरफ लाने की जिम्मेदारी भी सजातीय नेताओं को सौंपी गई है। भाजपा आलाकमान दलित मंत्रियों के साथ ही अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिसकी ओर अभी तक ना तो बीजेपी आलकमान और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान दिया है। इसमें सबसे बड़ा कारण पार्टी और सरकार के स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरी सरकार को अपने पास केन्द्रित कर लेना है। स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में योगी ही सब कुछ हो गये थे, यहां तक की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी जैसे जुमले बोलने लगे थे।

स्थिति यह हो गई थी कि जो वोटर अपने जनप्रतिनिधि से सीधे सम्पर्क में रहता है उसी जनप्रतिनिधि के अधिकारों को सीज कर दिया गया था,कई मौकों पर वह (विधायक/सांसद) अपने वोटरों को चाह कर भी इंसाफ नहीं दिला पाते थे, क्योंकि उनकी न तो सरकार में सुनवाई हो रही थी, न ही अधिकारी अथवा पुलिस उनकी सुनती थी। क्योंकि ऊपर से आदेश पास हुआ था कि कोई बीजेपी का नेता किसी सरकारी अधिकारी अथवा थाना-चौकी पर नहीं जायेगा। ऐसे में कोई नेता या जनप्रतिनिधि थाने-चौकी पर जाने की हिमाकत कर लेता था तो उसको बेइज्जत होना पड़ता था। नतीजा यह होता जनप्रतिनिधि अपने ही मतदाताओं की नजरों में उतर जाता। वह वोटरों से कटने लगता, जिसकी परिणिति लोकसभा चुनाव में हार के रूप में बीजेपी को चुकानी पड़ी।

अब जब बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है तो वह अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उनके द्वारा दलितों और ओबीसी समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी की वजहें गिनाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो कई मंत्रीं और नेता बेरोजगारी के अलावा पार्टी में जातीय कार्यकर्ताओं को तवज्जों न मिलना हार का एक बड़ा कारण बता रहे हैं।कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाये, जिससे दलित वोटरों में अच्छा मैसेज जायेगा। कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाये कि दलित अधिकारियों को थानेदारों और तहसीलदारों की नौकरियां तो मिलती हैं लेकिन उन्हें पोस्टिंग में दरकिनार रखा जाता है। पार्टी नेताओं ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्ट की नौकरी में दलित-ओबीसी समाज के लिए आरक्षण नहीं होने को राज्य में पार्टी की हार की बड़ी वजह बताया है। सरकार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज नेताओं ने कहा कि यह चिंतनीय है कि आखिर सरकार के बेहतर काम के बावजूद लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक तरीके से पहली बार बसपा से कट कर दलित वोट सपा और कांग्रेस की ओर चला गया, ऐसा आखिर क्यों हुआ इसका कारण बताते हुए नाराज नेताओं ने दलित नेतृत्व को आगे न बढ़ाने की बात रखी।

आज का राशिफल

मेष
आज लाभ का दिन है और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपको मेहनत करने से लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में निरन्तर परिश्रम करने से लाभ होगा। शाम के समय अतिथियों के आगमन से खर्च बढ़ेगा और आप काफी बिजी भी हो जाएंगे। सफलता के योग अच्छे हैं प्रयास करके सभी आवश्यक कार्य निपटा लें।

वृषभ
आज दिन सफलता से भरा होगा और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। किसी कार्य की अधिकता के कारण आपकी सेहत बिगड़ सकती है। खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें। कला व साहित्य में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से व्यवसाय में प्रगति होगी।

मिथुन
आज करियर में लाभ का दिन है और आपको मनचाही सफलता मिलने से भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सभी क्षेत्रों में बुद्धि और कौशल का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी समाप्त हो जाएगी और आपको संतान से करियर के मामले में लाभ होगा।

कर्क
आज आपको नौकरी और कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति होगी। बड़े बुजुर्ग की मदद से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। खर्च में कटौती करें नहीं तो कष्ट उठाना पड़ सकता है। कला-क्रीड़ा व साहित्य के क्षेत्र में आ रही बाधा दूर होने की संभावना है।

सिंह
आज करियर में लाभ होगा। पारिवारिक मामलों में खटपट हो सकती है। साहस और धैर्य से काम लेना होगा, किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और आपके कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा।

कन्या
आज दिन भाग्यशाली है और आपके आनंद में वृद्धि होगी और योजनाएं पूर्ण होंगी। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों को मेहनत करने से भरपूर लाभ होगा और नौकरीपेशा लोगों की आमदनी बढ़ेगी। परिवार में संपत्ति को लेकर भी कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है।

तुला
आज लाभ होगा और आपके पराक्रम व धन में वृद्धि होगी। किसी कानूनी मामले में आपकी जीत होगी और घर में पूरे दिन प्रसन्नता का माहौल रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। संपत्ति के व्यापार से लाभ होगा। संतान की सफलता के समाचार से आप आनंदित होंगी। शाम के समय किसी नए कार्य का आरंभ होगा।

वृश्चिक
आज सफलता के योग बन रहे हैं और आपको करियर के मामले में लाभ होगा। आपके प्रभाव प्रताप में वृद्धि होगी। व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र में परिश्रम, साहस की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष कमजोर होगा और आप सफल होंगे।

धनु
आज दिन लाभ देने वाला होगा। आपको संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार मिलेगा। नए-नए खर्चे निकलकर सामने आएंगे। कोई झूठा आरोप भी आप पर लग सकता है। शाम को लाभ होगा और भाग्य में वृद्धि के योग हैं। हर मामले में चौकन्ने रहें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय में लाभ होगा।

मकर
आज करियर के मामले में लाभ होगा और आपको कहीं से फंसी पेमेंट मिल सकती है। आपको सुव्यवस्था का कोई कार्य सौंपेगा। राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे। शिक्षा क्षेत्र में विशेष प्रगति होकर समाज में सम्मान मिलेगा। ऑफिस में आपके सामने कोई नया प्रस्ताव आए तो इस बारे में सोचकर ही फैसला करें।

कुंभ
आज दिन सावधानी से बिताने का है। लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। व्यय की अधिकता के कारण आज आपको किसी से कर्जा भी लेना पड़ सकता है और आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी कार्यकुशलता से और लोगों को प्रभावित करेंगे। सायंकाल के समय कोई विशेष कार्य निपट जाने से उत्साह बढ़ेगा।

मीन
आज आप अपने विरोधियों के लिए सिरदर्द बने रहेंगे। परिवार में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। इच्छित कार्यों की सफलता में चल रहा व्यवधान समाप्त हो जाएगा। रात्रि के समय किसी मंगल कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। आपका खर्च भी अधिक होगा और दौड़भाग भी करनी पड़ेगी।

संक्षिप्त समाचार

पुलवामा के बाद कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड से सबसे बड़ी शहादत, 348 से ज्यादा वीर सपूत हो चुके कुर्बान

देहरादून, एजेंसी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न ऑपरेशन में देश के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए उत्तराखंड के 348 से ज्यादा बहादुर बेटे अपने प्राणों की आहूति दे चुके हैं। यह संख्या उत्तराखंड बनने के बाद की है। इससे पहले के शहादतों को भी जोड़ा जाए तो यह संख्या 1700 तक है। बीते रोज जम्मू-कश्मीर के कठुआ हमले की घटना राज्य बनने के बाद की पहली घटना है, जब एक साथ राज्य के पांच सैनिक शहीद हुए हैं। पुलवामा आतंकी हमले के दौरान भी उत्तराखंड के चार सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उनकी शहादत अलग-अलग दिन हुई थी। सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार, अलग राज्य बनने से पहले वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में देश के 525 सैन्य अफसर और सैनिक शहीद हुए थे। इनमें 75 शहीद उत्तराखंड से थे। शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों के परिजनों तात्कालिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता और दो लाख रुपये आवासीय सहायता के रूप में देने का प्रावधान है। सेना मुख्यालय से शहादत के बारे में विस्तृत ब्योरा आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही शहीद के परिवार के एक सदस्य को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिलेगी।सरकार ने हर जिले में सृजित किए हैं पद राज्य के हर जिले में समूह 'ग' के कुछ पद सृजित हैं। सैनिक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार के स्तर पर तात्कालिक रूप से ये सहायता मान्य है। केंद्र सरकार के स्तर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता अलग है। केंद्र और राज्य के स्तर पर शहीदों के परिजनों के लिए कई और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

श्रावस्ती में भीषण हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर बाइक में लगी आग, 3 की मौत

श्रावस्ती, एजेंसी। श्रावस्ती में देर रात बाइक और ट्रैक्टर ट्राली में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इससे बाइक में आग लग गई। एक व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया और एक महिला सहित दो लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। तीनों मृतक नेपाल के निवासी थे। नेपाल राष्ट्र के जिला बांके के खास कुस्मा निवासी गोवर्धन घर्ती पुत्र खलीराम उम्र 26 साल, रामबहादुर 35 पुत्र केदार सिंह निवासी पुरना नाका जिला बाके नेपाल और कल्पना 30 एक बाइक से मंगलवार को भारतीय क्षेत्र में किसी रिश्तेदारी में आये थे। देर रात तीनों बाइक से वापस जा रहे थे। सिरसिया थाने के बेचुआ गांव के पास अचानक सामने से अनाज लदी ट्रैक्टर ट्राली आ गई। इससे दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। इसके कारण गोबरधन घर्ती की मौके पर मौत हो गई। सूचना पल पहुंची पुलिस ने दो घायलों को सीएचसी सिरसिया पहुंचाया जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

राजस्थान में अब घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर 1000 रुपए जुर्माना, जानिए जलदाय विभाग का आदेश

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राजस्थान जलदाय विभाग द्वारा पानी की लीकेज से लेकर घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। घरेलू पानी को व्यर्थ बहाने पर जलदाय विभाग ने नियम बनाएं हैं जिसमें पानी को बेवजह बहाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।जलदाय विभाग के मुताबिक, घरेलू पानी सप्लाई के जरीए पीने, नहाने, बर्तन और कपड़े धोने के काम में लाया जा सकेगा, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल घर के उद्यानों, सिचाई कार्य, भवन निर्माण, सार्वजनिक फव्वारे, स्विमिंग पूल, सजावटी कार्य या सजावटी कार्यों में किया जाता है तो इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस या आवासीय क्लब, थिएटर, सिनेमाघर और सड़कों पर पानी देने में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों को धोने में भी घरेलू पानी का उपयोग नहीं कर सकेंगे. कार्रवाई के लिए फील्ड पर इंजीनियर फोटो लेंगे और वीडियो बनाएंगे। इस सबूत को उपभोक्ता के खिलाफ कोर्ट में पेश किये जाएंगे। अगर पानी का दुरुपयोग साबित हो गया तो कोर्ट उपभोक्ता पर जुर्माना लगाएगा।

अयोध्या में जमकर जमीन खरीद रहे नेता-अफसर का परिवार, सात साल से नहीं बढ़ा है सर्किल रेट

अयोध्या, एजेंसी। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता खोलने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद अयोध्या में नेता से लेकर अफसर तक के परिवार में जमीन खरीदने की होड़ लगी है। लेकिन सात साल से यहां सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। खरीदारों में अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री चौना में, भाजपा नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के मुखिया अमिताभ यश जैसे वीआईपी का परिवार शामिल है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से मार्च 2024 तक राम मंदिर के आस-पास के 25 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री की 2500 रजिस्ट्री की पड़ताल के बाद दावा किया है कि इन इलाकों में जमीन की डील 30 प्रतिशत बढ़ गई है।

अखबार ने 18 वीआईपी फैमिली की जमीन खरीद का जिक्र किया है। इनमें चौना में, बृज भूषण शरण सिंह और अमिताभ यश के अलावा उत्तर प्रदेश के गृह सचिव व आईपीएस संजीव गुप्ता, यूपी के शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद पांडेय, रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद, आईपीएस अफसर पलाश बंसल, आईपीएस अफसर अनूप सिंह, रिटायर्ड डीजीपी यशपाल सिंह, सीबीएसई के पूर्व सचिव अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्या, यूपी के भाजपा नेता व विधायक अजय सिंह,

भाजपा नेता व गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल, भाजपा नेता व अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, बसपा नेता व पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू भैया, भाजपा नेता व पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, सपा नेता व पूर्व एमएलसी राकेश राणा और बसपा से भाजपा में शामिल पूर्व एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का परिवार शामिल है।

इनमें से किसी भी जमीन की खरीद में कोई गड़बड़ी रिपोर्ट नहीं की गई। कुछ खरीदारों ने तो जमीन बेच भी दी है। लेकिन अखबार ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट 7 साल से नहीं बढ़ाया गया है जिसके आधार पर स्टांप ड्यूटी तय होती है। वैसे अयोध्या ही नहीं यूपी के 75 में 54 जिलों में 2017 के बाद सर्किल रेट नहीं बदला है। जिलाधिकारी (डीएम) सर्किल रेट की हर साल समीक्षा करते हैं। सर्किल रेट के आधार पर ही अधिग्रहण की स्थिति में सरकार मुआवजा देती है। यूपी सरकार ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण पर सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दोगुना मुआवजा देती है।

अयोध्या के एक किसान दुर्गा प्रसाद यादव ने सर्किल रेट बढ़वाने के लिए 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका लगाई। राज्य सरकार ने 2022 में हाईकोर्ट को जवाब दिया कि 2018, 2019, 2020 और 2021 में सर्किल रेट की समीक्षा की गई थी लेकिन बाजार भाव 2017 जैसा ही था इसलिए कोई बदलाव नहीं हुआ। यूपी के स्टांप और रजिस्ट्रेशन के आईजी रूपेश कुमार ने अखबार को बताया कि 2022 और 2023 में अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि 2023 में 21 जिलों में सर्किल रेट बदला जिसमें अयोध्या के पड़ोसी जिले बस्ती और गोंडा शामिल हैं।

सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि आम तौर पर उन इलाकों में सर्किल रेट यथावत रखने की कोशिश होती है जहां सरकार को किसी परियोजना के लिए जमीन खरीदने की जरूरत हो ताकि मुआवजा में कम खर्च आए। अयोध्या में यूपी आवास विकास परिषद 1800 एकड़ का एक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मार्च तक 600 एकड़ की खरीद हो चुकी है और बाकी के अधिग्रहण का काम चल रहा है।

असम में बाढ़ के कारण छह गैंडों की मौत

गुवाहटी, एजेंसी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विनाशकारी बाढ़ ने 3,000 गांवों के 18 लाख लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. असम में अब तक कम से कम 72 लोगों और छह गैंडों की जान चली गई है.भारत के असम राज्य में बाढ़ न केवल हजारों गांवों के लिए विनाशकारी साबित हुई, बल्कि बाढ़ ने एक राष्ट्रीय उद्यान को भी अपनी चपेट में ले लिया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में एक बयान में कहा कि बाढ़ का प्रभाव अब कुछ हद तक कम होने लगा है. उन्होंने कहा, ब्रह्मपुत्र और उससे जुड़ी नदियों में जल स्तर बहुत खतरनाक स्तर से नीचे आ गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जून से सितंबर तक होने वाली मॉनसूनी बारिश गर्मी की तीव्रता को कम करने और पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर मॉनसून बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का कारण भी बनता है. हर साल बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है. हर साल बाढ़ का कहर हाल के सालों में बारिश और बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि हुई है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं. जैसे-जैसे पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का जल स्तर कम हो रहा है, क्षेत्र के वन्य जीवन पर आपदा के विनाशकारी प्रभाव साफ होने लगे हैं. असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से प्रभावित हुआ है. असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक,बाढ़ ने इंसान और जानवर दोनों को समान रूप से प्रभावित किया है सरमा ने सोशल मीडिया पर बाढ़ के पानी में फंसे एक गैंडे के बच्चे का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसकी ठुड्डी पानी में डूबी हुई थी सरमा ने लिखा कि उन्होंने अधिकारियों को उसे रेस्क्यू करने के निर्देश दिए थे. बाढ़ के कारण जंगली जानवरों की मौत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष ने बताया कि अब तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के पानी में डूबने से छह गैंडे, 100 हॉग डियर और दो सांभर की मौत हो गई जबकि 17 हॉग डियर, एक-एक स्वॉम्प डियर, रीसस मैकाक और ऊदबिलाव की देखभाल के दौरान मौत हो गई. उद्यान प्राधिकरण और वन विभाग ने बाढ़ के दौरान 97 जंगली जानवरों को बचाने में भी कामयाबी हासिल की है. राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन 233 में से 69 वन शिविर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं।

महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन, कार की टक्कर से 20 मीटर दूर गिरी महिला; मौत

नासिक, एजेंसी। पुणे में पोर्श कार, मुंबई में बीएमडब्ल्यू कांड के बाद अब महाराष्ट्र के नासिक से एक और हिट एंड रन का केस सामने आया है। यहां एक कार ने सड़क चलती महिला को तेज टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला काफी दूर जाकर गिरी। खास बात है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है। नाशिक में मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को चपेट में ले लिया। मृतका की पहचान वैशाली शिंदे के रूप में हुई है। खबर है कि टक्कर के बाद महिला 15 से 20 मीटर दूर जाकर गिरी थी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि महिला सड़क से गुजर रही है। तभी एक सफेद रंग की कार उन्हें टक्कर मार देती है। हादसे में घायल हुई 36 वर्षीय शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया था। अब खबर है कि पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने की घटना के दो दिन बाद फरार आरोपी 24 वर्षीय मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रहा था।

कोलकाता के राज्यपाल पर रेप का इल्जाम लगाने वाली डांसर ने कहा केस वापस नहीं लूंगी

कोलकाता, एजेंसी। पिछले साल अक्टूबर में बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस और उनके भतीजे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली ओडिसी डांसर ने यह साफ कर दिया है कि वह इस केस को वापस नहीं लेगी। एक बयान जारी कर उसने मामले को वापस लेने से साफ इनकार किया है। हालांकि उसने यह स्पष्ट किया है कि वह सक्रिय रूप से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसकी वजह यह है कि वह अमेरिका में भी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही है जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति और केंद्र के सामने लंबित है। उसने कहा है कि यह उसके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। उसने यह बयान तृणमूल के वरिष्ठ पदाधिकारी कुणाल घोष को जारी किया, जिन्होंने इसे फेसबुक पर शेयर किया है। गौरतलब है कि डांसर पहले अमेरिका में रहती थी। उन्होंने राज्यपाल और उनके भतीजे पर जनवरी 2023 में दिल्ली के होटल में यौन शोषण का आरोप लगाया था। कानूनी केस में उलझने के बाद वह वापस कोलकाता आ गई थी। उसने पुलिस को बताया कि अमेरिका के इसी कानूनी केस के लिए वह राज्यपाल से मदद मांगने आई थी।

उसकी शिकायत के आधार पर, हेयर स्ट्रीट पुलिस ने राज्यपाल के भतीजे के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक साजिश के लिए एक जीरो एफआईआर दर्ज की थी और इसे दिल्ली पुलिस को भेज दिया था। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है। उसने यह भी कहा कि वह राज्यपाल बोस से संबंधित शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं और इसके साथ

ही खराब स्वास्थ्य उसे इस समय राज्यपाल बोस से संबंधित मामले को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा है। घोष ने मंगलवार को डांसर का बयान पोस्ट किया जिस पर शिकायतकर्ता (राज्यपाल बोस जनवरी 2023 दिल्ली ताज होटल मामले के संबंध में) के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता को जानते हैं। उन्होंने प्रेस को बताया, उन्होंने मुझसे सही जानकारी देने के लिए संपर्क किया था क्योंकि कुछ गलत रिपोर्ट सामने आ रही थीं, जिनमें बिना नाम के गृह मंत्रालय अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि वह अपना मामला वापस ले रही हैं। उन्होंने आगे कहा, पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि वह अभी भी केस लड़ेंगी। हालांकि अमेरिका और भारत से जुड़े कुछ कानूनी केस के कारण वह इस समय मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। होटल में किया गया दुर्व्यवहार महिला ने पहले पुलिस को बताया था कि उसे विदेश यात्रा और डांस परफॉर्मेंस में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसने बोस से मदद के लिए संपर्क किया था। उसके अनुसार बोस ने उसे मदद का वादा करते हुए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहा था। इसके बाद उसे फ्लाइट टिकट भेजे गए और 5 और 6 जनवरी, 2023 को दिल्ली के एक होटल में ठहरने के लिए बुक किया गया। उसने पुलिस को बताया कि राज्यपाल उस समय दिल्ली के बंगाल भवन में ठहरे हुए थे और होटल में जब उससे मिलने आए थे तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

सिद्धारमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कर्नाटक में उनकी पत्नी और साले के खिलाफ पुलिस शिकायत

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक कांग्रेस और सरकार में डीके शिवकुमार के साथ वर्चस्व की लड़ाई का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं, जब उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैसूर जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और एमयूडीए के अधिकारी भूमि आवंटन घोटाले में शामिल हैं। कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर विवाद की जांच की मांग की है। स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत के अनुसार, सिद्धारमैया के साले मल्लिकार्जुन ने अन्य सरकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मदद

से 2004 में अवैध रूप से जमीन खरीदी और जाली दस्तावेजों के आधार पर इसकी रजिस्ट्री कराई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्वती, मल्लिकार्जुन और एक अन्य व्यक्ति ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल रूप से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कृष्णा ने कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत की रिसिविंग तो दी है लेकिन इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन होने के कारण अलग से प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। उन्होंने पुलिस से सात दिनों के भीतर उनकी शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कर्नाटक में भूमि आवंटन घोटाला सुर्खियों में रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी 2021 में भाजपा के कार्यकाल के दौरान एमयूडीए की लाभार्थी थीं। उस समय मैसूर के प्रमुख स्थानों में 38,284 वर्ग फुट भूमि उन्हें उनकी 3.16 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में आवंटित की गई थी। मैसूर के केसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें उपहार में दी थी। मुआवजे के तौर पर दक्षिण मैसूर में एक प्रमुख इलाके में उन्हें जमीन दी गई। आरोप है कि केसर गांव की जमीन की तुलना में इसकी कीमत काफी अधिक है। इसके कारण मुआवजे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। सिद्धारमैया ने इस भूमि आवंटन का बचाव करते हुए कहा है कि यह पिछली भाजपा सरकार के दौरान किया गया था।

लखनऊ में मुंशीपुलिया फ्लाईओवर बनकर तैयार, पांच लाख आबादी को मिलेगी राहत

लखनऊ , एजेंसी। लखनऊ में मुंशीपुलिया फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। करीब 1860 मीटर लंबे नवनिर्मित फ्लाईओवर से इंदिरानगर, खुर्रमनगर, विकासनगर सहित आसपास की पांच लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। पॉलीटेक्निक चौराहे से रिंग रोड जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2023 से मुंशीपुलिया फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया था। करीब 170 करोड़ की लागत से चार लेन नवनिर्मित फ्लाईओवर की खासियत यह है कि रिंग रोड की तरफ से आने वाले वाहन मुंशीपुलिया फ्लाईओवर पर चढ़कर सीधे अयोध्या रोड पर उतर सकेंगे। क्योंकि मुंशीपुलिया फ्लाईओवर को पॉलीटेक्निक फ्लाईओवर से जोड़ दिया गया है, लेकिन कमता की तरफ से आने वाले वाहन पॉलीटेक्निक फ्लाईओवर से उतरेंगे। लगभग 150 मीटर बाद मुंशीपुलिया फ्लाईओवर पर चढ़कर सीधे इंदिरानगर सेक्टर-16 पुलिस चौकी चौराहे पर उतरेंगे। पीडब्ल्यूडी (एनएच) ने फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट, व्यू कटर, रिफ्लेक्टर पट्टी सहित अन्य कार्य किया जा चुका है। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि मुंशीपुलिया फ्लाईओवर बनने से सीतापुर हाईवे से अयोध्या हाईवे का सफर आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंशीपुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। अभी लोकार्पण की तारीख तय नहीं है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव सुबह-शाम पीक आवर्स में रहता है, जिसकी वजह से इंदिरानगर डी-ब्लॉक, सेक्टर-12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 सहित आसपास के राहगीरों को 15 मिनट तो कभी लंबे जाम में फंसना पड़ता है। इससे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन पुल शुरू होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। सर्विस रोड पर बिजली के खंभे बने जानलेवा इंदिरानगर सेक्टर-16 पुलिस चौकी से मुंशीपुलिया चौराहे की तरफ आने पर सर्विस रोड पर बिजली के दो खंभे खड़े है। इससे डबल लेन रोड अचानक काफी संकरी हो जाती है। साथ ही तेज रफ्तार से आ रहे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद इन खंभों को हटाया नहीं गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक लेसा द्वारा शटडाउन न मिलने से पोल नहीं हट सकें थे। जल्द पोल हटा दिए जाएंगे। फ्लाईओवर से उतरते ही सड़क निर्माणकार्य अधूरा मुंशीपुलिया फ्लाईओवर से उतरते ही इंदिरानगर सेक्टर-16 पुलिस चौकी तक सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है। साथ ही नाला निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर सर्विस रोड बनकर तैयार हो जाएगी।

महाराष्ट्र में बाजी पलट रही है! अबकी बार एनडीए विधायक रहेंगे होटल में और विपक्ष बेफिक्र

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद दो साल बीत चुके हैं। उनके बाद पिछले साल ही अजित पवार भी चाचा शरद पवार से बागी हो गए थे और फिर सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। लोकसभा चुनाव से पहले तक इन घटनाक्रमों के चलते विपक्ष बैकफुट पर दिख रहा था, लेकिन 30 सीटें हासिल करने के बाद अब चीजें बदल गई हैं। राज्य में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव है और 12 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। इससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग होगी। ऐसी स्थिति में दोनों खेमों की ओर से कोशिश है कि अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए और दूसरे के तोड़ लिए जाएं। इस कोशिश में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें होटलों की बुकिंग शुरू कर दी है। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार से ज्यादा बेचैनी इस बार एनडीए खेमे में है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि एनडीए के पास ज्यादा विधायक है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास तो अब एक-एक दर्जन विधायक ही बच होंगे। वहीं कांग्रेस भी बेफिक्र दिख रही है। उसने गुरुवार को विधायकों के लिए लंच का आयोजन किया है, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे विधान परिषद चुनाव में वोटिंग करनी है। वहीं भाजपा,

एकनाथ शिंदे सेना और अजित पवार गुट होटलों की बुकिंग में जुटे हैं ताकि विधायकों को एकसाथ रखा जा सके। ऐसा इसलिए कि क्रॉस वोटिंग का डर है। खासतौर पर एकनाथ शिंदे सेना और अजित पवार के विधायकों के टूटने का डर है। लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आई हैं कि विधायक अपनी वफादारी फिर से बदल सकते हैं। इसलिए इन्हें होटलों में रखने की कोशिश है। हालांकि अनंत अंबानी के विवाह के चलते मुंबई में फाइव स्टार होटल फुल हैं और कमरे मिलना मुश्किल हो रहा है। इस शादी के लिए लिए देश-विदेश से वीआईपी मेहमान आए हुए हैं। इसलिए साउथ मुंबई इलाके के ज्यादातर फाइव स्टार होटल बुक हो चुके हैं। अब खबर है कि भाजपा और शिवसेना के विधायकों को अलग-अलग ठहराया जा सकता है। बता दें कि उद्धव सेना ने मिलिंद नार्वेकर को उतारा है, जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि एकनाथ शिंदे सेना के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर ले। इस चुनाव में पैसों का खेल चलने की आशंका भी तेज है। हालांकि इसके चलते डर सभी दलों में है। अब तक की जानकारी के अनुसार विधायकों को मुंबई से थोड़ा बाहर के इलाकों में रखा जा सकता है और ये वोटिंग से ठीक पहले लाए जाएंगे।

में कोपा अमेरिका: 2024

कनाडा को हराकर अर्जेंटीना कोपा अमेरिका के फाइनल

● मेसी ने दागा 109वां गोल

ईस्ट रदरफोर्ड (न्यू जर्सी), एजेंसी। लियोनेल मेसी के अपने करियर के 109वें अंतरराष्ट्रीय गोल और वर्तमान टूर्नामेंट के पहले गोल के दम पर गत चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 2-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। अर्जेंटीना की तरफ से जूलियन अल्वारेज ने 22वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि मेसी ने 51वें मिनट में एन्जो फर्नांडीज के शॉट को गोल में भेज कर उसकी बढ़त दोगुनी की।

मेसी के सामने तब गोलकीपर मैक्सिम क्रेप्यू थे लेकिन इस स्टार फुटबॉलर के आगे उनकी एक नहीं चली। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने पिछले 25 मैचों में 28 गोल किए हैं। वह कोपा अमेरिका में अब तक 14 गोल कर चुके हैं जो रिकॉर्ड से तीन गोल कम हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में मेसी से अधिक गोल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर दर्ज हैं जिन्होंने अभी तक 130 गोल किए हैं। ईरान के अल देई के नाम 1993 से 2006 तक 108 या 109 गोल दर्ज हैं।

इक्वाडोर के खिलाफ 2000 में किए गए उनके गोल को लेकर विवाद है क्योंकि इस मैच के अंतरराष्ट्रीय दर्जे को लेकर मतभेद हैं। अर्जेंटीना ने यह जीत अपने स्वतंत्रता दिवस पर हासिल की जिससे उसका अजेय अभियान 10 मैच तक पहुंच गया है। अर्जेंटीना रविवार को होने वाले फाइनल में उरुग्वे या कोलंबिया का सामना करके रिकॉर्ड 16वां कोपा खिताब जीतने की कोशिश करेगा।

राहुल द्रविड़ ने जीता दिल
बीसीसीआई से मिले अतिरिक्त बोनस को ठुकराया

नई दिल्ली, एजेंसी। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। यह बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इस सोच को सच साबित करते हैं राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज जो पैसों को नहीं बल्कि स्पिरिट ऑफ गेम को अहमियत देते हैं। टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच द्रविड़ से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है, जिससे एक बार फिर उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। द्रविड़ ने कई बार अपनी निस्वार्थ शैली के लिए प्रशंसा बटोरी है। क्रिकेट की दुनिया में राहुल द्रविड़ की पहचान अपने खेल के दिनों से एक शानदार खिलाड़ी के साथ-साथ एक अच्छे इंसान के रूप में भी है। बतौर, कोच भी उनका सफर शानदार रहा। चाहे खिलाड़ी युवा हो या अनुभवी हर कोई उनके व्यक्तित्व की सराहना करता है। अपनी निस्वार्थ शैली का ताजा उदाहरण पेश करते हुए द्रविड़ ने एक और मिसाल कायम की है। राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के दौरान उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने तीन आईसीसी फाइनल खेला। दो बार बेहद करीब से ट्रॉफी से चुकने के बाद आखिरकार टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2024 जीतकर अपने कोच को यादगार विदाई दी। इस खुशी के मौके पर बीसीसीआई द्वारा टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए घोषित 125 करोड़ रुपये की राशि में से 5 करोड़ रुपये की विजेता टीम के मुख्य कोच यानी राहुल द्रविड़ को देने का ऐलान किया लेकिन द्रविड़ ने पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा छोड़ने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपये मिले थे। जबकि टीम के अन्य कोचों को 2.5 करोड़ रुपये दिए जाने थे। ऐसे में द्रविड़ ने फैसला किया है कि वह भी अन्य कोचों की ही तरह 2.5 करोड़ लेंगे।

यानी द्रविड़ ने अपने सहयोगी स्टाफ के बराबर बोनस लेने का फैसला किया। केंसिंग्टन ओवल में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर सात रन की रोमांचक जीत के साथ भारत द्वारा 2024 पुरुष टी20 विश्व कप जीतने के एक दिन बाद, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि टीम को कुल 125 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वितरण फार्मूले के अनुसार, मुख्य कोच द्रविड़ और टीम के सभी 15 सदस्यों को 5-5 करोड़ रुपए मिलने थे। जबकि बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच टी. दिलीप और गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे सहित अन्य सहयोगी स्टाफ को 2.5-2.5 करोड़ रुपए मिलने थे। हालांकि, द्रविड़ ने अन्य सहयोगी स्टाफ को दिए जाने वाले इनाम के साथ अपने बोनस में 2.5 करोड़ रुपए लेने से इनकार कर दिया। राहुल अपने सहयोगी स्टाफ (गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे, फील्डिंग कोच टी.दिलीप और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर) के बराबर ही बोनस राशि (2.5 करोड़ रुपए) चाहते थे। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब द्रविड़ ने पुरस्कारों के समान वितरण के लिए रुख अपनाया है। 2018 में भारत की विजयी अंडर-19 विश्व कप टीम के मुख्य कोच के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान द्रविड़ ने ऐसा ही कुछ किया था।

उस समय द्रविड़ को 50 लाख रुपये मिलने थे, जबकि सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों को 20-20 लाख रुपये मिलने वाले थे। ऐसे में द्रविड़ ने इस तरह के विभाजन से इनकार कर दिया, जिससे बीसीसीआई को इस बोनस में थोड़ा बदलाव करना पड़ा और सभी को समान रूप से पुरस्कृत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोर्ड ने इसके बाद नकद पुरस्कारों की संशोधित सूची जारी की, जिसमें द्रविड़ सहित सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 30 लाख रुपये दिए गए।

पंजाब ने नामीबिया को चौथे वनडे मैच में 33 रन से रौंदा

मोहाली, एजेंसी। नामीबिया दौरे पर पंजाब की युवा टीम ने लगातार चौथी जीत दर्ज की और वनडे सीरीज में 4-0 लीड बना ली। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266/10 रन बनाए और जवाब में नामीबिया टीम 233/10 रन ही जोड़ सकी। पंजाब ने 33 रन से मैच जीता। फिरकी गेंदबाज जस इंदर सिंह ने मेजबान टीम के पांच विकेट झटके और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

चौथे मैच में पंजाब ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पुखराज मान के साथ अनमोलप्रीत सिंह ने 51 रन की साझेदारी पहले विकेट के लिए की। अनमोलप्रीत 30 रन बनाकर लौट गए। इसके बाद कप्तान नमन धीर ने पुखराज मान का साथ दिया। दोनों ने 92 रन जोड़े। नमन धीर 56 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि पुखराज मान ने 79 रन पर 61 रन की पारी खेली।

भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने पर बोले गौतम गंभीर

मैं वापस आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं

नई दिल्ली, एजेंसी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़ टीम इंडिया में ये भूमिका निभा रहे थे। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल टी20 विश्व कप 2024 के बाद समाप्त हो गया। भारतीय टीम ने द्रविड़ की कोचिंग में विश्व कप का खिताब जीता। अब गौतम गंभीर टीम के नए हेड कोच के तौर पर काम करेंगे। गंभीर इससे पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के मेंटर की भूमिका में थे और उनके मार्गदर्शन में केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गंभीर को हेड कोच बनाए जाने की पुष्टि कर दी है। गौतम गंभीर ने भी अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तिरंगे की फोटो लगाते हुए लिखा, भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। मैं वापस आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, इस बार मेरी टोपी अलग है। लेकिन, मेरा लक्ष्य हमेशा से वही है, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। मेन इन ब्लू के कंधों पर 1.4 अरब भारतीयों के सपने हैं, और मैं इन सपनों को साकार करने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूंगा। इसके पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं बेहद प्रसन्नता के साथ गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच के तौर पर स्वागत करता हूं। आधुनिक क्रिकेट बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और गंभीर ने इस बदलाव को काफी करीब से देखा है। गंभीर ने अपने करियर में जितनी भूमिका को निभाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए गौतम गंभीर एक आदर्श व्यक्ति हैं। भारतीय टीम के लिए उनका स्पष्ट नजरिया, उनका पुराना अनुभव, उन्हें कोचिंग के रोल के लिए एकदम सही बनाता है। बीसीसीआई का उनको पूरी तरह से सहयोग रहेगा। बता दें कि गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 टूर्नामेंट जीता था।

ये केकेआर की आईपीएल में तीसरी ट्रॉफी थी। खास बात ये है कि केकेआर की टीम ने तीनों ट्रॉफी गंभीर के साथ ही जीती है। इससे पहले गंभीर ने बतौर कप्तान आईपीएल में केकेआर को दो बार खिताबी जीत दिलाई थी। आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम का मेंटर बनने से पहले गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मेंटर थे। 42 साल के गौतम गंभीर ने 58 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 41.96 की औसत के साथ 4,154 रन बनाए हैं। उन्होंने 147 वनडे मुकाबलों में 39.68 के साथ 5,238 रन बनाए हैं। इसके अलावा गंभीर को 37 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का भी अनुभव है, जिसमें उन्होंने 27.41 की औसत के साथ 932 रन बनाए हैं। गौतम गंभीर ने अपने करियर में 154 आईपीएल मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 31.04 के औसत के साथ 4,218 रन बनाए हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेगा।

तेलंगाना सरकार का ऐलान

सिराज को सरकारी नौकरी और घर की जगह देने की घोषणा

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देश और राज्य को बड़ा सम्मान दिलाने वाले हरफनमौला क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और घर के लिए जगह देने की घोषणा की है। टी20 विश्वकप जीतकर लौटी भारतीय टीम का हिस्सा रहे सिराज का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सिराज में मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टी-20 में बेहतरी प्रदर्शन के लिए सिराज की प्रशंसा की और सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से सिराज को नौकरी और घर की जगह आवंटित करने का भी निर्देश दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने हैदराबाद या आस-पास के इलाकों में तुरंत सिराज के लिए उपयुक्त घर की जगह की पहचान करने और उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिये है।

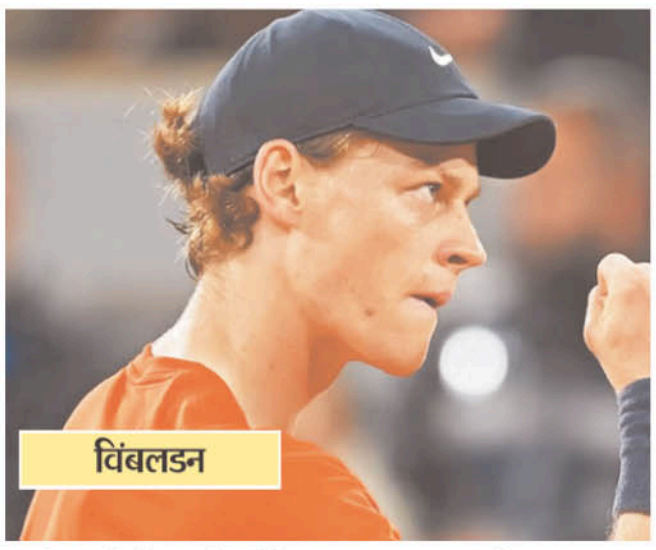

मेदवेदेव के खिलाफ हार के साथ शीर्ष वरीय सिनर विंबलडन से बाहर

लंदन, एजेंसी। शीर्ष वरीय यानिक सिनर को दानिल मेदवेदेव ने पांच सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर मंगलवार को यहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मेदवेदेव ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए सिनर को 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6, 6-3 से हराया। सिनर के इस मुकाबले के दौरान अपने ट्रेनर से उपचार लेना पड़ा और वह तीसरे सेट में कोर्ट से चले गए थे। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिनर को क्या हुआ था। लॉकर रूम में जाने से पहले उनकी हृदय गति की जांच भी की गई। इटली का यह 22 वर्षीय खिलाड़ी लगभग 10 मिनट बाद वापस लौटा और फिर से खेलना शुरू किया।

डोना वेकिच पहली बार ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में

क्रोएशिया की 28 वर्षीय खिलाड़ी डोना वेकिच ने मंगलवार को यहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में तीन सेट तक चले मुकाबले में लुलु सन को हराकर पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वेकिच ने न्यूजीलैंड की क्वालीफायर सन को 5-7, 6-4, 6-1 से हराया।

फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में

16 साल के स्पैनिश फुटबॉलर यमाल ने रचा इतिहास

यूरो कप:2024

बर्लिन, एजेंसी। 16 वर्षीय लामेन यमाल यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मंगलवार को म्यूनिख में खेले गए सेमीफाइनल में यमाल और दानी ओल्मो की गोल की बदौलत स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हरा दिया और यूरो 2024 के फाइनल में जगह बनाई। रैंडल कोलो मुआनी के नौवें मिनट में किलियन एम्बाप्पे के क्रॉस पर किए गए गोल से पिछड़ते हुए स्पेन ने चार मिनट के अंदर ही मैच का पासा पलट दिया। स्पेन ने इस टूर्नामेंट में पिछले पांच मैचों में केवल एक गोल खाने वाली टीम के खिलाफ चार मिनट के अंदर दो गोल दागे और फिर से इस बढ़त को कायम रखते हुए जीत हासिल की। यमाल यूरो कप फाइनल से एक दिन पहले अपना 17वां जन्मदिन मनाएंगे। अब फाइनल में स्पेन का सामना बर्लिन में नीदरलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। यमाल ने बॉक्स के बाहर से शानदार स्ट्राइक कर गोल दागा और स्पेन को बराबरी करने में मदद की। गेंद फ्रांस के गोलकीपर माइक मैग्नन की अंगुलियों को छूते हुए गोलपोस्ट में चली गई। स्पेन ने 25वें मिनट में बढ़त बना ली जब दानी ओलमो ने नेट में गेंद को पहुंचा दिया। मिडफील्ड गेम मैनेजमेंट के मास्टर्स स्पेन ने बढ़त लेने के बाद डिफेंसिव खेल दिखाया। काउंटर अटैक के बजाय बॉल पजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया। तीन बार का चैंपियन स्पेन यूरो कप में छह मैच जीतने वाली पहला देश बन गया है और वह रिकॉर्ड चौथे खिताब से एक मैच दूर है। पिछले चार मेजर टूर्नामेंटों में से तीन में फाइनलिस्ट फ्रांस से जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि वह कैसे आक्रामक फॉरवर्ड के बावजूद फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा। कोच डिडिए डेशां ने एंटोनी ग्रीजमैन को तरजीह देने की बजाय ओस्मान डेम्बेले को लगातार मौका दिया। इसके अलावा जीरूड को भी बेंच पर बैठाए रखा। फिट नहीं होने के बावजूद एम्बाप्पे लगातार खेलते रहे।

यमाल का प्रदर्शन इस यूरो कप में शानदार रहा है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में एक गोल के अलावा तीन असिस्ट भी किए हैं।

पीसीबी ने दो दिग्गजों की कर दी छुट्टी!

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त फिर के बदलाव के दौर से गुजर रहा है। टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम से मिली हार और सुपर 8 में भी एंट्री ना कर पाने के बाद इस तरह के परिवर्तन की संभावना पहले ही जताई जा रही थी। जो अब शुरू भी हो गई है। इस बीच ईएसपीएन क्रिकइन्फो के हवाले से पता चला है कि पीसीबी ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो सेलेक्टर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि अभी तक पीसीबी ने इसको लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक ये भी हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ और भी बदलाव आने वाले वक्त में भी देखने के लिए मिल सकते हैं।

वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक की सेलेक्शन कमेटी से छुट्टी – पाकिस्तान के टी20 विश्व कप 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेलेक्टर के रूप में वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को बर्खास्त कर दिया गया है। अब्दुल रज्जाक को कुछ सप्ताह पहले ही पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए चयन समिति में नियुक्त किया गया था, अब महिला टीम के लिए भी चयनकर्ता के रूप में काम नहीं करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेलेक्शन कमेटी फिर से नए सिरे से बनाए जाने की संभावना है। अभी तक पीसीबी ने सेलेक्शन कमेटी में चीफ सेलेक्टर का पद ही खत्म कर दिया था, जो अब फिर से बनाए जाने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि सेलेक्शन कमेटी में सदस्यों की संख्या भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। वहाब रियाज ने टी20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान की टीम के साथ सीनियर टीम मैनेजर की भी भूमिका निभाई थी। पीसीबी चीफ ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टीम ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो किसी भी भी कुर्सी पर खतरा आ सकता है, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस न करे।

ग्राम पंचायत स्तर की जनसुनवाई में ग्रामीणजनों में दिखा उत्साह, बड़ी संख्या में आवेदनों का मौके पर हुआ निराकरण

पन्ना। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की शिकायतों व समस्याओं के तत्काल समाधान के उद्देश्य से जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन की पहल पर अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणजनों से आवेदन प्राप्त करने के उपरांत तत्काल सुनवाई कर शिकायतों का मौके पर त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इस क्रम में आज सुबह 11 से 1 बजे तक सभी पांच जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई में ग्रामवासियों के आवेदनों का बड़ी संख्या में मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया गया। किन्हीं कारणोंवश तत्काल समस्या का समाधान संभव नहीं होने पर कुछ आवेदनों को संबंधित विभाग के

अधिकारी को न्यूनतम समय-सीमा में निराकरण के लिए प्रेषित किया गया। गुनौर जनपद पंचायत की समस्त 80 ग्राम पंचायतों में प्राप्त 258 आवेदनों में से 215 का निराकरण आवेदक की उपस्थिति में करने की कार्यवाही की गई। शाहनगर जनपद पंचायत की 84 ग्राम पंचायत में आज की जनसुनवाई में 133 आवेदन प्राप्त हुए। अजयगढ़, पन्ना एवं पवई जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई में भी अधिक संख्या में आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा जिले के दूर दराज क्षेत्रों के आवेदकों के जनसुनवाई में जिला मुख्यालय तक आवागमन तथा स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई व्यवस्था की शुरूआत कर सुव्यवस्थित तरीके से कार्यवाही के लिए संबंधित लोक सेवकों को निर्देशित किया गया है। जिला अधिकारियों को सभी अधीनस्थ लोकसेवकों को जनसुनवाई के लिए पाबंद करने के निर्देश भी दिए गए थे। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर की जनसुनवाई की मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की ड्यूटी भी निर्धारित की गई है। जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं।

ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई में मंगलवार को पहुंचे आवेदकों में उत्साह देखा गया। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में तत्परतापूर्वक समस्या का निराकरण होने से ग्रामीणजनों ने जिला प्रशासन की सराहनीय व अभिनव पहल की प्रशंसा भी की गई। स्थानीय ग्रामीणजनों ने कहा कि ग्राम पंचायत व विकासखण्ड स्तर पर जनसुनवाई की शुरूआत होने से अब जिला मुख्यालय तक अनावश्यक आवागमन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस शुरूआत से समय की बचत होने के साथ कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी मिला है।

जिला कलेक्टर की पहल पर ग्राम पंचायतों में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होने पर अब जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या भी कम हुई है। आवेदनों के ग्राम पंचायत स्तर पर निराकरण होने से पुरानी व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का असर भी दिखा है। आज कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई में मात्र 21 आवेदन आए। यहां अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र द्वारा जनसुनवाई कर आवेदनों पर तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया गया।

अनियमितता करने वाले तहसीलदार पर कमिश्नर ने कार्यवाही करने के दिये निर्देश

कलेक्टर ने एसडीएम को सौपी जांच

पन्ना। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में पदस्थ तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर मनमाने तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और नियम कानूनो की धज्जियां उडाते हुए मनमाने ढंग से शासकीय कार्यो को किया जा रहा है। उक्त मामले को लेकर स्थानीय समाजसेवी सुरेश कुमार लोभवशी द्वारा कमिश्नर सागर को शिकायत की गई थी, जिसके परिपेक्ष मे कमिश्नर सागर ने वीरेन्द्र कुमार रावत द्वारा कलेक्टर को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देशो पर कलेक्टर सुरेश कुमार ने एसडीएम अजयगढ को जांच करने की जिम्मेवारी दी है। आवेदक ने आवेदन मे उल्लेख किया था कि तहसीलदार श्री अहिरवार द्वारा मनमाने ढंग से नामांतरण प्रकरण स्वीकृत किये गये तथा जैतपुर के 132 केवि स्टेशन कें लिए अधिग्रहित भूमियो को बिना कलेक्टर की अनुमति के बगैर फर्जी तरीके से स्वीकृतियां दी गई। साथ ही रिश्वत के रूप में राशि लेकर अपात्रो के बीपीएल कार्ड बनाये गयें एवं उक्त बीपीएल कार्ड आरसीएम पोर्टल के मूल आदेश की कॉपी की जगह ब्लैक पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तहसील कार्यालय में निराकरण प्रतिशत बढ़ाने के लिए फर्जी केस डिस्पोजल किए गए हैं, बरौली गांव में कई संपन्न व्यक्तियों के फर्जी बीपीएल कार्ड बनाए जाने की जानकारी का उल्लेख किया गया है। तहसील कार्यालय अजयगढ में इनके खास व्यक्तियों एवं दलालो के माध्यम से ही कोई भी कार्य हो सकता है। यदि कोई भी आवेदक इनके दलालो से नही मिलता है तो उसका कोई कार्य तहसील कार्यालय से नही होता है। आंगे देखना है कमिश्नर के निर्देश के बाद संबंधित तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है।

समाजसेवी शिक्षक राम चरण सेन की पुण्यतिथि आज, परिवारजनो ने किया याद

पन्ना। अजयगढ निवासी शिक्षक तथा समाजसेवी राम चरण सेन की पन्द्रवी पुण्य तिथि पर उनके परिवारजनों एवं रिस्तेदारो ने याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान अनेक लोग उपस्थित रहें। जिसमें मुख्य रूप से उनके परिवारजन अशोक कुमार, ललित, अरूण, राजवर्धन, रश्मी आदि।

किसानों को कृषि योजनाओं के लिए एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

पन्ना

कृषि विभाग की विभिन्न योजना अंतर्गत बीज, सिंचाई यंत्र एवं आदान सामग्री का लाभ लेने के लिए जिले के कृषक किसान पोर्टल एमपी किसान पर ऑनलाइन पंजीयन करायें। पंजीयन के लिए वेबसाइट के माध्यम से स्वयं या नजदीकी एमपी ऑनलाइन पर जाकर आवेदन करें। किसान पोर्टल पर कृषि योजना के लिये पंजीयन पर क्लिक करें। कृषि योजना के लिये पंजीयन लिंक पर क्लिक करने के बाद नए टैब में पंजीयन पेज ओपन हो जाता है तथा पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज जो संलग्न होने की जानकारी दी जाती है जैसे कृषक का आधार कार्ड, कृषक की भूमि से संबंधित जानकारी, कृषक की समग्र आईडी, कृषक का जाति प्रमाण-पत्र यदि आवेदक अनु. जाति, अनु. जनजाति का हो तो जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करने के बाद किसान पंजीयन फार्म प्रदर्शित हो जाता है जहां दो ऑप्शन प्रदर्शित होते है। आधार नंबर द्वारा पंजीयन अथवा भू-अभिलेख द्वारा पंजीयन करें आप्शन में से किसी एक ऑप्शन के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं अथवा नजदीकी एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी अपना पंजीयन व आवेदन करा सकते हैं। इस वर्ष कृषि विभाग के ऑनलाईन पोर्टल एमपी किसान पर अपने आवेदन का पंजीयन उपरांत ही कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। कृषक बंधुओं से ऑनलाईन पोर्टल एमपी किसान पर अपना आवेदन पंजीयन कराने की अपील की गई है।

तहसील स्तरीय जनसुनवाई में आए 42 आवेदन

पन्ना। मंगलवार को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सम्पन्न हुई जनसुनवाई में प्राप्त कुल 805 आवेदनों में से 678 आवेदनों का मौके पर निराकरण करने की कार्यवाही की गई है, जबकि शेष 127 आवेदनों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। आज ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में सर्वाधिक 258 आवेदन गुनौर विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त हुए, जिसके तहत 215 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। इसी तरह पन्ना विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 177 आवेदनों में से 142 का, अजयगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 134 आवेदनों में से 123 का, पवई विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 103 आवेदनों में से 99 का तथा शाहनगर विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 133 आवेदनों में से 99 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

अफसर शाही से परेशान जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सदस्यों ने किया सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार

कहा-कांग्रेस सरकार के पंचायती राज को भाजपा ने किया समाप्त

पन्ना। जिले मे अधिकारीयों की मनमानी चरमसीमा पर चल रही है। भाजपा की सरकार मे चुनें हुए जन प्रतिनिधियों की भारी उपेक्षा हो रही है। जिससे भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा के जन प्रतिनिधि भारी परेशान है। क्योकि उनकी कोई भी अधिकारी सुनने वाला नही है। इन्ही तमाम उपेक्षाओं को लेकर जिला पंचायत मे आयोजित समान्य सभा की बैठक का बहिस्कार जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यो द्वारा करते हुए मुख्यमंत्री के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सदस्यों के अनुमोदन के बिना कोई भी कार्य स्वीकृत न हो, रोजगार सहायक, सचिव एवं उपयंत्री के स्थानान्तरण जिला पंचायत समिति के द्वारा ही किये जाये। नमामी गंगे योजना के जो कार्य स्वीकृत किए गए है, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की

अनुमति के बगैर न हो। धारा 52 में जिला पंचायत के कृत्यों, अधिकार एवं शक्तियों का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया जा रहा है। जिले की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना जिला पंचायत की साधारण सभा का संवैधानिक दायित्व हैं। शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षको की भर्ती जिला पंचायत के माध्यम से ही किये जाये। शिक्षकों की निलंबन एवं बहाली के संबंध में अवगत कराया जाये। निर्माण कार्यों के मूल्याकन के समय माप पुस्तिका में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर कराये जाए। उक्त तमाम सात बिन्दुओं को लेकर बहिस्कार किया गया है। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि सन् 1993 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। जिसमें जन प्रतिनिधियो को अधिकार संपन्न बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय मे हम लोगो की घोर उपेक्षा की जा रही है तथा किसी भी प्रकार से कही भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को सम्मान नही मिल रहा है और न ही अधिकार मिल रहें है। ज्ञात हो कि जिले भर में ग्राम पंचायतो मे चल रहें निर्माण कार्यो मे व्याप्क स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। लोगो द्वारा लगातार शिकायते करने के बावजूद संबंधितो पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। चारो तरफ अरजक्ता का महोल कायम है। ज्ञात हो कि भाजपा कि जिला पंचायत परिषद है तथा प्रदेश मे भाजपा की सरकार है उसके बावजूद उक्त जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सिर्फ नाम के लिए पद पर बनें हुए है।

इनका कहना है

हम लोगो की लगातार उपेक्षा हो रही है, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, सभी कार्य अधिकारीयों द्वारा किये जा रहें है, जिसको लेकर सामान्य सभा की बैठक का बहिस्कार किया गया है तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सात बिन्दुओं का दिया गया है, यदि हम लोगो को अधिकार नही दिये गये तो आंगे भी बैठको मे शामिल नहीं होगें।

मीना राजे अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा अधिकारो को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेगें तथा जो भी सम्मान जन प्रतिनिधियो का होता है उसमे किसी प्रकार की कोई कमी नही होगी।

संघ प्रिय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सलेहा में किराना दुकानों का किया निरीक्षण

पन्ना। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीतू खरे ने सलेहा नगर की किराना दुकानो एवं मिष्ठान होटल का निरीक्षण किया। इस दौरान सलेहा में गैस एजेंसी के पास गर्ग किराना दुकान का निरीक्षण किया एवं उक्त दुकान से खाद्य तेल का सेम्पल लिया गया। बस स्टैंड में स्थित लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता की किराना दुकान से कुरकुरे का नमूना जांच हेतु लिया गया। खाद्य अधिकारी नीतू खरे के अनुसार उक्त खाद्य सामाग्री के सेम्पल जांच के लिए भेजे जायेगें तथा रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

बीड़ी श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना

पन्ना। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट व लौह-मैग्नीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनांतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति की राशि रुपये 1000 से अधिकतम रुपये 25000 तक प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र-छात्राओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया 30 जून से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि प्री-मैट्रिक हेतु 31 अगस्त एवं पोस्ट मैट्रिक हेतु 31 अक्टूबर निर्धारित है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए ओटीआर व फेस ओथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। आवेदन की पात्रता व संबंधित अन्य जानकारी व शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करने के पश्चात् अपने शिक्षण संस्थान में संपर्क कर अपने आवेदन को स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करवाना जरूरी है।

बबूल के पेड़ से लटका मिला महिला का शव

पन्ना। जिले के शाहनगर थाना अन्तर्गत ग्राम चौपरा मे 28 वर्षीय महिला सलोचना पति विनोद रैकवार का शव गांव के बाहर खेत में बबूल के पेड़ मे लटका हुआ पाया गया। जिसे लोगो ने देखा तथा घटना की जानकारी परिजनो को दी गई। परिजनो ने मामले के संबंध में शाहनगर पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही शाहनगर पुलिस घटना स्थल पंहुचे तथा शव को पेंड़ से उतारकर पंचनामा बनाया एवं उसका पोस्ट मार्टम कराया गया। मामले के संबंध में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। वहीं दूसरी ओर मायके पक्ष द्वारा ससुराल वालो के उपर मारपीट करने तथा प्रताडित करने के भी आरोप लगाये है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर आज

पन्ना। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड संभाग पन्ना कार्यालय द्वारा गुरूवार, 11 जुलाई को पन्ना (शहर) वितरण केन्द्र धरमसागर में वृत्त/जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया है। शिविर का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है। इस मौके पर शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। कार्यपालन यंत्री द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से शिविर में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर बिजली बिल, मीटर, लाइन और अन्य विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण कराने की अपील की गई है।

जनसंख्या समाधान फाऊंडेशन की जिला सयोजक बनी उर्मिला कुशवाहा

पन्ना। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष हेमांगी अरोरा द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए पन्ना जिले मे संयोजक का दायित्व श्रीमती उर्मिला कुशवाहा को सौपा गया है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डाइट में किया गया पौधारोपण

पन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत आज डाइट पन्ना में पौधारोपण किया गया जहां पर पीपल बरा सहित अन्य फलदार पौधे रोपित डाईट पन्ना मे रोपित किये गये। इस अवसर पर वार्ड नंबर 13 की पार्षद कविता चाणक्य रैकवार, जिला शिक्षा अधिकारी रवि खरे, पार्षद प्रतिनिधि नीरज लोधी, युवा मोर्चा जिला मंत्री अंकित रैकवार, गो संवर्धन बोर्ड के जिला उपाध्यक्ष संतोष चाणक्य रैकवार, रोकी पांडेय, उमेश रेले, प्रमोद, कीर्ति खरे, हरिराम माली, भानु प्रताप खरे, सुधा मिश्रा, चैताली चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांत निगम, संजीव श्रीवास्तव, शिवांश यादव, मनोज कुमार, बाबू लाल रैकवार, रामदास वर्मा, राजेश श्रीवास्तव, गोरेलाल अहिरवार, सपना शर्मा, सहित अधिकारी कर्मचारी गण एवं कार्यकर्ता कारण उपस्थित रहे।

नशामुक्ति अभियान के क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय के निर्देशानुसार नशीले पदार्थों तथा शराब के सेवन से नशामुक्ति के उद्देश्य से सतत् रूप से नशामुक्ति अभियान के सक्रिय क्रियान्वयन के लिए जिला एवं अनुभाग स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति द्वारा नशामुक्ति कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष और उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सदस्य-सचिव होंगे, जबकि बतौर सदस्य पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, वनमंडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीएमओ नगर पालिका परिषद पन्ना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला संयोजक, जिला शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र, जिला आबकारी अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला योजना अधिकारी सहित दो अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इसी तरह अनुभाग स्तर की समिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अध्यक्ष और समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि बतौर सदस्य अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं वन, जनपद पंचायत सीईओ, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, खण्ड शिक्षा अधिकारी, संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी और दो अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि को दायित्व सौंपा गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हितग्राहियों के ई-केवायसी सत्यापन 15 जुलाई तक

पन्ना। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर सत्यापन किया जा रहा है। इसके तहत जिले में शेष हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर ई-केवायसी किया जा रहा है। ई-केवायसी में हितग्राहियों का पुन: जिलेवार सत्यापन की तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार की वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन सहित 6 प्रकार की पेंशन योजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिनका ऑनलाइन क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजनाओं के हितग्राहियों का आधार ई-केवाईसी अप्रैल 2023 से निरंतर जारी है।

मशीनो से कराये जा रहें निर्माण कार्य, मजदूर कर रहे पलायन

आठ लाख की रिकवरी होने के बावजूद नही हुई जिम्मेवारो पर कोई कार्यवाही

पन्ना। जिले में ग्राम पंचायतो मे भ्रष्टाचार चरमसीमा पर चल रहा है। निर्माण कार्य मशीनो से कराये जा रहे है तथा फर्जी मस्टर रोल मजदूरो के नाम डालकर राशि आहरित की जा रही है। इसी प्रकार का मामला शाहनगर जनपद पंचायत अन्तर्गत ग्राम पंचायत टूडा का प्रकाश मे आया है। स्थानीय उपसरपंच तथा अन्य ग्रामवासीयों द्वारा कलेक्टर को जन सुनवाई मे दिये गये आवेदन मे उल्लेख किया गया कि, ग्राम टुडा मे दस लाख की राशि से तालाब जीर्णोदार का कार्य स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य मजदूरो के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है। लेकिन सरपंच, सचिव, रोजगार, सहायक, उपयंत्री द्वारा जेसीबी मशीन तथा ट्रैक्टरो के

माध्यम से कार्य कराया जा रहा है एवं फर्जी मस्टर रोजगार सहायक द्वारा जारी कर फर्जी हाजरी भरी जा रही है। आवेदन में उल्लेख किया गया कि विगत एक जुलाई से लेकर सात जुलाई तक मस्टर रोल मे प्रतिदिन 85 लेबर लगाकर खोदाई कार्य किया जा रहा है। जबकी मौके पर एक भी लेबर उपस्थित नही मिली। सभी कार्य जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से कराया गया है। ग्राम पंचायत सरंपच श्रीमती दीवीबाई चौधरी, सचिव अर्जुन सिंह तथा रोजगार सहायक शिव चरण चौधरी है जो सरपंच देवीबाई के पति है। रोजगार सहायक शिव चरण का स्थानान्तरण भी ग्राम पंचायत पुरैना हो गया है, उसके बावजूद उसके द्वारा ही मस्टर जारी किये जा रहें है तथा पंचायत का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्राम टुडा में खेर माई स्थान से लेकर सूरज राय के घर तक नाली स्वीकृत हुई थी। जिसमें तीन लाख रूपये की राशि आहरित की गई। जबकी 50 मीटर तक नाली का निर्माण नही कराया गया है। उन्होने यह भी आरोप लगाया कि जिस तालाब में जल संवर्धन के तहत जीर्णादार कार्य चल रहा है। उक्त तालाब का जीर्णोदार कार्य पूर्व में वर्ष 21-22 में भी हो चुका है। जबकी शासन के स्पष्ट निर्देश है कि पांच वर्ष पहले जिस तालाब मे निर्माण कार्य हुआ है, उसमें फिर से नही करवाया जाये। लेकिन सरपंच सचिव द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कार्य स्वीकृत कराया गया है साथ ही जेसीबी मशीन के माध्यम से तालाब के बीच के पार मे मिट्टी डाल देने के कारण ग्राम वासीयों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है।

सरपंच पति शिव चरण द्वारा फर्जी मस्टर भरकर व्याप्क स्तर पर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। पूर्व में उक्त सरपंच, सचिव, उपयंत्री द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो मे किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी। जिसमें संबंधितो के खिलाफ जिला पंचायत न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए नौ लाख रूपये की राशि की रिकवरी निकाली गई थी। जिसका प्रकरण चल रहा है। स्थानीय लोगो ने ग्राम पंचायत मे कराये गये कार्यो की जांच कराने तथा दोषीयो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

सिटी टाइगर

विन्ध्य टाइगर | सीधी, गुरूवार 11 जुलाई 2024 | 8

बाल भवन रीवा में बच्चों ने भगवान जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष में चित्रकला के माध्यम से भगवान के चित्र बनाएं और उनमें तूलिका से रंग भरे। इन चित्रों में बच्चों ने खूबसूरती के साथ प्रकृति को भी दर्शाया तथा पत्ते पर भगवान का चित्र उकेरा जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

संक्षिप्त खबरें

लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित

रीवा। जिले के दो लोक सेवा केन्द्रों के संचालन के लिए पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट आपरेटरों के चयन हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गयी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निविदा प्रपत्र लोक सेवा केन्द्रों की जिले की बेवसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन निविदा का प्रकाशन एवं डाउनलोड 11 जुलाई को किया जा सकता है। ऑनलाइन निविदा 31 जुलाई तक भरी जा सकती तथा निविदा 2 अगस्त को खोली जायेगी।

संभाग स्तरीय बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य : कमिश्नर

रीवा। कमिश्नर रीवा संभाग बी.एस. जामोद ने संभाग स्तरीय बैठकों में अधिकारियों की अनिवार्यतः उपस्थिति के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जिन संभागीय कार्यालयों में संभागीय अधिकारियों की पदस्थापना न हो वहां जिला स्तरीय अधिकारी ही नोडल अधिकारी होंगे तथा वह संभागीय बैठकों में सभी जिलों से जानकारी संकलित कर बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

गौशालाओं की पूर्णता एवं संचालन की जानकारी भेजे : कलेक्टर

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने गौसंवर्धन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित गौशालाओं की पूर्णता एवं संचालन की जानकारी भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में गौशालाओं का सीईओ जनपद, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं इच्छुक स्वसहायता समूह व गैर शासकीय संस्थाओं के साथ बैठक कर पूर्णता का भौतिक सत्यापन करते हुए कार्ययोजना प्रस्तुत करें। साथ ही सड़कों में घूम रहे पशुओं को गौशाला में प्रतिस्थापन हेतु कार्ययोजना तैयार करायें।

आहरण संवितरण अधिकारियों का आईएफएमआईएस साफ्टवेयर का प्रशिक्षण 22 जुलाई से

रीवा। जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के विधिवत एवं सुचारू संचालन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रशिक्षण 22 जुलाई से 27 जुलाई तक दिया जायेगा। कार्यालयों में वित्तीय संव्यवहार आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रशिक्षण में स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि वित्तीय संव्यवहार सुगमतापूर्वक किया जा सके। प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने की स्थिति में संबंधितों को कारण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

शांति समिति की बैठक आज

रीवा। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 11 जुलाई को शाम 5 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल करेंगी। बैठक में मोहर्रम, रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी पर्व त्यौहारों के आयोजन के संबंध में किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी।

किसान फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें : उप संचालक कृषि

किसानों को डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग की सलाह

रीवा

जिले के कृषकों को सलाह दी गई है कि वह डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरकों का प्रयोग करें। कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी सलाह में कहा है कि डीएपी में केवल दो तत्व नाइट्रोजन व फास्फोरस प्राप्त होते हैं। जबकि एनपीके उर्वरक से फसलों के लिए आवश्यक सभी तीन मुख्य पोषक तत्वों नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश की उपलब्धता होती हैं। इस प्रकार एनपीके उर्वरक से नत्रजन एवं स्फुर के अलावा पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व पोटाश की पूर्ति किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अतः एनपीके उर्वरक का प्रयोग करने पर किसान भाईयों को अलग से पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ती है व लागत में कमी आती है। उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने किसान भाईयों के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद का उपयोग करने की सलाह दी है। उप संचालक ने कहा है कि फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग लाभदायक होता है। डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके का उपयोग अधिक लाभदायी है। इससे जमीन को सल्फर की प्राप्ति होती है। सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग खेत की तैयारी के समय किया जाता है। जिससे यह फसलों में अधिक कारगर रहता है। डीएपी में उपलब्ध 18 प्रतिशत नाइट्रोजन में से केवल 15 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 46 प्रतिशत फास्फोरस में से 39 प्रतिशत फास्फोरस पानी में घुलकर मिट्टी को प्राप्त होता है। शेष फास्फोरस मिट्टी में जमा हो जाता है जिससे मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घटती है। उप संचालक ने बताया है कि आगामी फसल में शंकर धान एवं शंकर मक्का के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश एनपीके खाद का उपयोग अधिक लाभकारी होगा। दलहन एवं तिलहन फसलों में 80:40:30 एनपीके तथा सल्फर का उपयोग लाभदायी होगा।

उप संचालक ने बताया है कि किसान नैनो तकनीक पर आधारित खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। फसलों के लिए 20 प्रतिशत नाइट्रोजन से युक्त नैनो यूरिया तथा 8 प्रतिशत नाइट्रोजन एवं 16 प्रतिशत फास्फोरस से युक्त नैनो डीएपी उपलब्ध है। इनके निर्धारित मात्रा में उपयोग से फसलों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4 प्रतिशत तक होती है। फसलों की बढ़वार की स्थिति में इनमें नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का पत्तियों में छिड़काव करने से पौधों को कारगर तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता हो जाती है। इनके उपयोग से पैदावार में वृद्धि होती है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल 225 रुपए में तथा नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की बोतल 600 रुपए में मिल रही है। इसकी कीमत एक बोरी खाद से लगभग आधी है। जबकि इसका असर एक बोरी खाद से भी अधिक है। इसलिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग किसानों के लिए अधिक लाभकारी है।

सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए जनपद पंचायत जवा में रोजगार मेले का आयोजन आज

रीवा। एसआईएस द्वारा जिले के सभी जनपद मुख्यालयों में सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सुरक्षा अधिकारी के पद हेतु इच्छुक बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण के उपरांत संस्था द्वारा स्थाई रोजगार से जोड़ा जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ सोनवणे ने बताया कि जनपद पंचायत जवा में 11 जुलाई को सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। रोजगार मेले में 19 वर्ष से 40 वर्ष आयु के 10वीं कक्षा पास/फेल 167.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के युवा शामिल हो सकते हैं। संस्था द्वारा 350 रूपये पंजीयन शुल्क जमा करने तथा चयनित होने के पश्चात प्रशिक्षण का व्यय 10 हजार रूपये प्रशिक्षण केन्द्र सिंगरौली पर स्वयं करना होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संभाग में 11 लाख 25 हजार परिवार हुए लाभान्वित

रीवा। पात्र परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू की गई है। इस योजना के प्रथम चरण तथा दूसरे चरण का कार्य पूरा होने के बाद रीवा संभाग में 11 लाख 25 हजार 168 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। योजना के तीसरे चरण में पात्र परिवारों के आवेदन पत्र प्राप्त कर उनके ई केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। अब तक तीसरे चरण में संभाग में 59 हजार 157 आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं।

इस संबंध में प्रभारी आपूर्ति अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्रेयश गोखले ने बताया कि उज्ज्वला योजना से रीवा तथा मऊगंज जिले में छः लाख 52 हजार 811 परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इनमें से दो लाख 84 हजार 543 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। तीसरे चरण में अब तक 22 हजार 114 आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। सतना तथा मैहर जिले में पाँच लाख 78 हजार 370 परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इनमें से चार लाख 91 हजार 266 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। तीसरे चरण में अब तक 10 हजार 726 आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं।

सीधी जिले में दो लाख 88 हजार 94 परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इनमें से एक लाख 75 हजार 884 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। तीसरे चरण में अब तक 15 हजार 354 आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। सिंगरौली जिले में दो लाख 86 हजार 538 परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इनमें से एक लाख 73 हजार 475 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। तीसरे चरण में अब तक 10 हजार 963 आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं।

मत्स्य कृषक दिवस का आयोजन सम्पन्न

रीवा। मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र लखोरीबाग रीवा एवम सिरमौर प्रक्षेत्र में मछुआरों को समिति के सही तरीके से संचालन , मत्स्य बीज संचयन एवं बंद ऋतु काल में मत्स्याखेट नही करने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी समिति सदस्यो से 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया।

सहायक संचालक डॉ अंजना सिंह द्वारा सभी समिति सदस्यो को अपने आस पास एवम तालाबों के किनारे वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। मछुआ दिवस के अवसर पर चार हितग्रहियों को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालन के लिए स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, अनुसूचित जन जाति के हितग्राही को मछली विपणन हेतु फिश कियोस्क सेंटर के लिए 50 हजार का केसीसी एवं अनुसूचित जन जाति के एक हितग्राही को मत्स्य परिवहन हेतु थ्री व्हीलर वाहन के लिए अनुदान का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी, मछली व्यापारी एवम समिति सदस्य उपस्थित रहे।

पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई 23 जुलाई को

रीवा। मऊगंज जिले के हनुमना तहसील के ग्राम बीरादेई में 1.091 हेक्टेयर जमीन में पत्थर उत्खनन के लिए आवेदन दिया गया है। इसमें कुल 12 खसरा नम्बर शामिल हैं। खदान की मंजूरी के पूर्व इसकी पर्यावरणीय जन सनुवाई के लिए 23 जुलाई 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर मऊगंज के प्रतिनिधि के रूप में अपर कलेक्टर अशोक ओहरी ग्राम पंचायत भवन परिसर बीरादेई में 23 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से सुनवाई करेंगे। सुनवाई में क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा तथा खदान के लिए आवेदन करने वाली मेसर्स शिवकृपा एसोसिएट के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

दस्तक अभियान में हर विकासखण्ड में लगेंगे दो-दो शिविर

रीवा

जिले भर में 27 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एएनएम तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर पाँच साल तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच कर रही हैं। जाँच के दौरान डायरिया, निमोनिया, एनीमिया से पीड़ित, जन्मजात विकृति एवं कम पोषित बच्चों का चिन्हांकन किया जा रहा है। अभियान के दौरान बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण और विटामिन ए का घोल पिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि अभियान के दौरान चिन्हित बच्चों के उपचार के लिए सभी विकासखण्डों में दो-दो स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन शिविरों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। शिविरों में पर्याप्त दवाओं के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों के दल तैनात करें।

कलेक्टर ने बताया कि 18 जुलाई को हनुमना विकासखण्ड के पीएचसी पिपराही, जवा में पीएचसी डभौरा, सिरमौर में सीएचसी सेमरिया, त्योंथर में सीएचसी चाकघाट, गंगेव में पीएचसी लालगांव तथा सीएचसी गोविंदगढ़ में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह 15 जुलाई को सीएचसी नईगढ़ी, मऊगंज विकासखण्ड के पीएचसी ढेरा तथा सीएचसी रायपुर कर्चुलियान में शिविर लगेंगे। जिले में 10 अगस्त को सीएचसी हनुमना, सीएचसी जवा, सीएचसी सिरमौर, सीएचसी त्योंथर, पीएचसी गंगेव, सीएचसी नईगढ़ी तथा पीएचसी रहट में शिविर लगाए जाएंगे। मऊगंज विकासखण्ड में 12 अगस्त को पीएचसी देवतालाब तथा रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड में सीएचसी गुढ़ में शिविर लगेंगे। सीएचसी मऊगंज में 21 अगस्त तथा शहरी क्षेत्र रीवा के लिए जिला अस्पताल रीवा में 22 जुलाई को शिविर लगेगा। इन शिविरों में शिशु रोग विशेषज्ञ, आरबीएसके की टीम तथा अन्य तकनीशियन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

रीवा संभाग में 209 गौशालाओं में हैं 31780 गौवंश

रीवा। निराश्रित तथा असहाय गौवंश को आश्रय देने के लिए मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना से गौशाला का निर्माण किया गया है। इनका संचालन ग्राम पंचायतों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। रीवा संभाग में 209 संचालित गौशालाओं में 31 हजार 780 गौवंश को आश्रय दिया गया है। प्रत्येक गौशाला में गौवंश के लिए चारा, भूसा, पानी, छाया तथा उपचार की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में प्रभारी संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा ने बताया कि संभाग में मनरेगा योजना से निर्मित 184 गौशालाओं में 16 हजार 710 गौवंश हैं। अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 25 गौशालाओं में 15 हजार 105 गौवंश को आश्रय दिया गया है। मनरेगा से जिन गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है उनके संचालन के लिए ग्राम पंचायत से अनुबंध करके गौवंश रखने की व्यवस्था की जा रही है। ऐरा प्रथा से खेती को हानि होने के साथ पशुओं के दुर्घटना का कारण बनने की घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए पशुपालकों को भी पशुओं को घर पर रखने की समझाइश दी जा रही है।

संयुक्त संचालक ने बताया कि रीवा जिले में मनरेगा योजना से निर्मित 95 गौशाला में 8 हजार 145 तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित चार गौशलाओं में 6 हजार 733 गौवंश हैं। सतना जिले में मनरेगा से संचालित 56 गौशालाओं में 4 हजार 816 तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित 16 गौशालाओं में 7 हजार 819 गौवंश हैं। सीधी जिले में मनरेगा से संचालित 19 गौशालाओं में एक हजार 988 तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित तीन गौशालाओं में 310 गौवंश हैं। सिंगरौली जिले में मनरेगा से संचालित 14 गौशालाओं में 1761 एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित दो गौशालाओं में 243 गौवंश हैं।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जगह-जगह हुआ पौधारोपण

रीवा। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जिले भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी शिक्षण संस्थानों एवं कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस अभियान में भागीदारी निभाकर जगह-जगह पौधे रोपित कर रही हैं। इस क्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने तहसील कार्यालय गुढ़ का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय परिसर में पौधे रोपित किए। इस अवसर पर एसडीएम गुढ़ डॉ अनुराग तिवारी तथा तहसीलदार विनयमूर्ति शर्मा ने भी पौधे रोपित किए। वृक्षारोपण अभियान के तहत

गत दिवस गायत्री शक्तिपीठ रीवा में भी पौधे रोपित किए गए। शक्तिपीठ के आचार्यों तथा स्वयंसेवकों ने औषधीय पौधों का रोपण किया। डॉ रामसुजान सिंह स्मृति समिति की अध्यक्ष डॉ ज्योति सिंह ने सहयोगियों के साथ विश्वविद्यालय स्टेडियम के समीप हमार बिरवा माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित कर 250 फलदार और छायादार पौधे रोपित किए।

बाल भवन के बच्चों ने की मनमोहक चित्रकारी

रीवा। बाल भवन रीवा में बच्चों ने भगवान जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष में चित्रकला के माध्यम से भगवान के चित्र बनाएं और उनमें तूलिका से रंग भरे। इन चित्रों में बच्चों ने खूबसूरती के साथ प्रकृति को भी दर्शाया तथा पत्ते पर भगवान का चित्र उकेरा जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। चित्रकला में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया।

श्री विधि से धान की रोपाई किसानों के लिये वरदान

रीवा। जिले में काफी बड़े क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। अधिकतर किसान रोपा विधि से धान लगाते हैं। इसकी तुलना में मेडागास्कर विधि जिसे एस.आर.आई. श्री विधि कहा जाता है, से धान लगाना अधिक लाभकारी है। इसमें कम पानी, कम बीज और बिना खरपतवार के धान का अच्छा उत्पादन होता है। परम्परागत विधि से किसान को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल धान की उपज मिलती है। इसकी तुलना में श्री विधि से धान लगाने पर प्रति हेक्टेयर 35 से 50 धक्कटल धान का उत्पादन होता है। उप संचालक यूपी बागरी कृषि ने किसानों से धान रोपण के लिये श्री विधि अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक किसानों के लिये वरदान है।

उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि श्री विधि से प्रति हेक्टेयर केवल 6 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। इसे विशेष तरह की प्लेट अथवा पॉलीथीन में नर्सरी लगाकर तैयार किया जाता है। इसमें भुरभुरी मिट्टी तथा राख का होना आवश्यक है। इसके लिये 10 मीटर लम्बी तथा 5 से.मी. ऊंची क्यारी बनायें। इसमें 50 किलो नाडेप अथवा गोबर की खाद मिलाकर बीजों की बोनी करें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

रीवा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन म.प्र. के आह्वान पर जिला इकाई रीवा के द्वारा सिरमौर चौराहा रीवा से एक रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश महासचिव किशोरी वर्मा, जिलाध्यक्ष शशी कला, जिला महासचिव रामबती सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर रीवा के माध्यम से प्रधानमंत्री को आंगनवाड़ी कर्मियों की विभिन्न लंबित मांगों के निराकरण हेतु आठ सूत्रीय ज्ञापन तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्री म.प्र.शासन एवं आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र.भोपाल के नाम सोलह

सूत्रीय ज्ञापन के साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रीवा को छःसूत्रीय ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि परियोजना अधिकारी रायपुर कर्चुलियान परि.क्र.1 द्वारा दिनांक 31.05.2024 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें 41 आंगनबाड़ी कर्मियों का 5-5 दिन का मानदेय काटा गया जिसमें कार्य में कमी का विवरण में सम्पर्क ऐप में केन्द्र नहीं खोले जाना बताया गया, जबकि संपर्क ऐप में कमी के कारण किसी का मानदेय नहीं काटा जा सकता। यदि कोई ऐसा आदेश है कि सम्पर्क ऐप में कमी के कारण मानदेय काटा जायेगा तो कृपया आदेश उपलब्ध कराये, सेक्टर बैठक के दिन सिलपरा सेक्टर में निरीक्षण किया गया, केन्द्र में कार्यकर्ता न मिलने के कारण 3 से 5 दिन का मानदेय काट लिया गया जबकि कार्यकर्ता कार्य करते हुए बैठक में उपस्थित थीं। इस तरह काम करने के बाद भी मानदेय काट लिया गया अतः मानदेय कटौती बंद करते हुए काटे गये मानदेय का भुगतान कराया जाय, लाडली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत कार्यकर्ता को प्रमाण पत्र निकलवाकर लाने को कहा जाता है वहीं पैसों का भुगतान भी कार्यकर्ता को ही करना पड़ता है जो न्याय संगत नहीं है कृपया ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाय, रायपुर परियोजना क्र.1 में पोर्टल की लिंक में लाडली लक्ष्मी की ई केवाईसी चेक करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गयी है सभी से मोबाईल में इतना काम नहीं बन पाता। ऐसी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर न डाली जाय, प्रधानमंत्री मात्र बंदना योजना के मानदेय का भुगतान कराया जाय, आंगनवाड़ी कर्मियों को बैठकों, ट्रेनिंग व केन्द्र के अलावा अन्यत्र कहीं भी बुलाया जाय तो नियमानुसार टी.ए.डी.ए.का भुगतान कराया जाय।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक राजेन्द्र तिवारी द्वारा एस आर के प्रिंटिंग प्रेस विवि रोड खुटेही रीवा से मुद्रित कर जीडीसी के सामने उत्तरी करौदिया सीधी से प्रकाशित। संपादक-राजेन्द्र तिवारी , आर.एन.आई नं. 47589/88 , डाक पंजीयन : MP/SDL/DN/-30/2015-17, दूरभाष : 09424315633,7389444833